Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

Discussion on working of the Ministry of Water Resources

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we take up the discussion on the working of the Ministry of Water Resources. Shri Keshubhai Patel.

श्री केशुभाई सवदास भाई पटेल (गुजरात): माननीय उपसभापति महोदय, इस सदन में वॉटर रिसोर्सिज़ के ऊपर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं सबसे पहले मैं यह बात कहूंगा कि हमें आजादी मिली, हमने आयोजन शुरू किए। 1950 से हम शुरू करें तो आज करीब 55-56 साल बीत गए हैं और 55-56 सालों के बाद हम इस हिन्दुस्तान के या भारत के गांवों और शहरों की ओर अगर नज़र डालें तो क्या दृश्य हमें देखने को मिलता है? खास करके बड़े शहर हों या टाउन्स, जिनको हम नगर कहते हैं.. ऐसे नगर हों या बड़े शहर हों, ऊपर जब हम नज़र डालते हैं, तो वहां जनसंख्या की वृद्धि बड़ी तेज़ी से हो रही है। जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, उसमें भी यदि गौर से देखा जाए तो गंदी बस्तियों और झोंपड़-पट्टीयों की संख्या तो शहर में और तेज़ी से बढ़ रही है। मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि ये झोपड़-पट्टियां पहले नहीं थीं, अब बन गईं। ये गंदी बस्तियां पहले नहीं थीं, अब बन गईं। इनमें बसने वाले लोगों से जाकर यदि आप पूछें कि भाई, तुम यहां झोपड़-पट्टियों में कब से रह रहे हो, तो कोई कहेगा कि दो साल से हूं, कोई कहेगा कि पांच साल से हूं, कोई कहेगा कि आठ-दस साल से हूं कोई पुराना होगा तो पंद्रह-बीस साल की बात करेगा, कोई बहुत ही पुराना होगा तो पच्चीस-तीस साल से होगा। यानी करीब तीस साल से लेकर आज तक, इस बीच के काल में नगरों में और बड़े नगरों में बहुत तेज़ी से लोग बाहर से आए। कौन हैं वे लोग? कहां से आए हैं वे? वे हैं ग्रामों में बसने वाले लोग। वे क्या करते थे? वे खेत-मज़दूर थे, छोटे किसान थे या मार्जिनल किसान थे। वे क्यों आए यह सब छोड़कर, इन गंदी बस्तियों या इन झोंपड़-पट्टियों में रहने के लिए? क्योंकि वहां रोज़गार नहीं है। वे कहते हैं कि हम लोग खाएं कहां से? जब रोज़गार नहीं है तो खाने के लिए कुछ तो चाहिए। हम तो मेहनतकश लोग हैं। मेहनत करनी है तो फिर शहरों की ओर दौड़ते हैं। एक सर्वे ने बताया है कि गंदी बस्तियों में लोग कम आयु में मर जाते हैं, यानी कम से कम आयु किस क्षेत्र में है? तो वह शहरी क्षेत्र में नहीं है क्योंकि वहां अच्छा वातावरण नहीं हो सकता, ग्रामीण क्षेत्र में भी नहीं है, आदिवासी क्षेत्र में भी नहीं है। कम से कम आयु वाले हैं गंदी बस्तियों में। कितनी मजबूरी है, मर जाते हैं। कीचड़

में कोई कीड़ा पैदा होता है और चालीस-पचास-साठ साल में वह कीचड़ में ही मर जाता है। क्यों आए तुम वहां से? क्योंकि रोज़गार नहीं है। रोज़गार क्यों नहीं हे? ज़मीन तो है तुम्हारी वहां पर? ज़मीन तो है, लेकिन ज़मीन में पानी नहीं है। हमारे पास पानी नहीं है, इरिगेशन के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए भी पानी नहीं हैं।

आज तीस साल के बाद हमारी यह हालत है। हम कहीं पर भी देखें, दक्षिण के शहरों में देखें, उत्तर शहरों में देखें, पश्चिम या पूर्व के शहरों में देखें, आदिवासी क्षेत्र के अंदर भी जो शहर हैं, वहां देखें और पहाड़ी क्षेत्रों के शहरों में भी देखें, यही दृश्य सर्वत्र, हमें पूरे देश में देखने को मिलेगा। आज आदमी पानी के लिए तरसता है। पानी के लिए शहरों में बड़ा दंगल हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। टैंकर से पानी मिलता है। पानी टैंकर से बेचा जाता है। आज ऐसे हालत के दृश्य हम देख रहे हैं।

माननीय उपसभापति जी, हम सब लोग दुखी हैं। हमें उसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। यदि पहले से ही सही नीति तय की होती तो ये हालात नहीं होते। ऐसा तो नहीं है कि बरसात पहले आती थी, अब नहीं आती। पहले भी बरसात आती थी, आज भी बारिश होती है। कभी-कभी सूखा भी पड़ जाता है और कभी-कभी ज्यादा बारिश भी होती है। प्रकृति तो हमको बारिश देती है, पानी देती है, लेकिन इस पानी को धरती पर रोक देना, डैम बनाकर, अलग-अलग उपायों से पानी को रोकना, पूरे के पूरे पानी को रोकना, इस परिस्थिति का निपटारा करने का यही उपाय है। महोदय, क्या मैं बैठ जाऊं। इतनी देर तक खड़ा रहा, लेकिन अब खड़ा नहीं रहा जाता।

श्री उपसभापति: आप बैठ जाइए, बैठकर बोलिए।

श्री केशुभाई सवदास भाई पटेल: माननीय उपसभापति जी, पानी है, लेकिन पूरे पानी का उपयोग हम लोगों ने नहीं किया है। मैं एक ही बात कहूंगा कि आज हम जिस बजट की चर्चा करने जा रहे हैं, हम वाटर रिर्सोसेज के ऊपर विचार कर रहे हैं।

[उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) पीठासीन हुए]

यदि इस बजट पर नजर डाली जाए तो कुल मिलाकर अपना एक साल का केन्द्रीय बजट कितने रूपए का है, यह 2,11,524 करोड़ का है। वाटर रिर्सोसेज के ऊपर आंकड़ा कहता है कुल बजट रखा हुआ है, 624 करोड़ रूपया, तो आप कहेंगे कि यह तो राज्यों का सब्जैक्ट है। हम राज्यों का सब्जैक्ट कहकर, अपनी जिम्मेदारी टाल सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कितने ही डिपार्टमेंट हैं, जो सब्जैक्ट राज्यों का होता है, लेकिन हम इसके ऊपर ज्यादा पैसा, ज्यादा खर्च कर रहे हैं, लेकिन 2,11,524 करोड़ रुपए के कुल खर्चे में से 621 करोड़ रुपया, और कोई कहेंगे कि कर्जा दिलवाएंगे, हां कर्जा दिलवाते हैं, राज्यों का विश्व बैंक के जरिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जरिए, जो अपनी संस्थाएं हैं, उनके जरिए.....।

वह पैसा मिलता है, लेकिन राज्यों के ऊपर बोझ कितना है, प्रदेशों के ऊपर कितना बोझ है, यह स्थिति हम मिटा नहीं पाएंगे। जो हो गया सो हो गया, अब इसे रोकना है। गांव वाले जो पलायन करते हैं, अगर उन्हें रोकना हैं तो वहां पानी देना पड़ेगा। यह हो सकता है, मैं कहता हूं कि यह हो सकता है। हमारे देश में इतना पानी है, लेकिन उसका सुचारू रूप से उपयोग करना चाहिए। मैं एक के बाद एक प्वाइंट ले रहा हूं। आज की परिस्थिति राष्ट्र के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। इससे पेयजल, सिंचाई, उद्योग के लिए पानी की उपलब्धि कम हो रही है। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो विकास की संभावनाएं और कम हो जाएंगी। जब हर व्यक्ति को प्रतिवर्ष मिलने वाला जल एक हजार क्यूबिक मीटर से कम हो जाता है तब उसका विकास भी रुक जाता है। मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। विश्व की जो पॉप्युलेशन है, उसके हिसाब से 16 प्रतिशत पॉप्युलेशन भारत की है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी) पीठासीन हुए]

विश्व में जो टोटल पानी है, उसका 4 प्रतिशत पानी हमारे पास है। देखिए, दुनिया के कम्पेरिजन में हम कहां पर हैं, मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज स्थिति ऐसी है कि पानी तो है, लेकिन कहां है? गंगा नदी के बेसिन में, ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में, मेघना नदी के बेसिन में है। देश की पॉप्युलेशन इस बेसिन के आसपास 1/3 है, इनके पास पानी 2/3 है। बाकी इस क्षेत्र को छोड़कर जो पूरा देश है, वह 2/3 है। इनके पास जमीन 2/3 है लेकिन पानी 1/3 है। यह बात सोचकर एन॰डी॰ए॰ की सरकार ने रीवर जोड़ने का, नदियों को एक-दूसरे से जोड़ने का कार्यक्रम बनाया। यह कार्यक्रम आगे चला, तीन साल तक चला। मैं बजट देख रहा था तो मुझे बहुत दुख हुआ। इसमें मैंने देखा कि इस साल के बजट प्रवचन में, डॉक्यूमेंट में जितना बल इस पर देना चाहिए, उतना बल यू॰पी॰ए॰ सरकार ने नहीं दिया है। यह बड़े दुख की बात है। क्या इसके पीछे राजनीतिक कारण है? क्या कोई व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न है? मैंने आंकड़े दिए हैं। इन आंकड़ों को देखकर कोई भी कह सकता है कि 2/3 वाला क्षेत्र, जहां बाढ़ आती है। जिन क्षेत्रों में बाढ़ से फसल चौपट हो जाती है, उनको बचाना है तो इस पानी को नीचे ले जाना पड़ेगा, देश के मध्य भाग में ले जाना पड़ेगा, पश्चिमी भाग में ले जाना पड़ेगा, दक्षिणी भाग में भी ले जाना पड़ेगा। इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों में नदियों को जोड़ना पड़ेगा। इस कार्यक्रम को एन॰डी॰ए॰ सरकार ने बहुत तेजी से आगे बढ़ाया था लेकिन मैंने कहा कि इस प्रकार की जो स्थिति है, मेरा अनुरोध है कि इसको राजनीति की दृष्टि से न देखा जाए। मैंने पूर्व भूमिका में वर्णन किया है कि एक-एक बूंद के लिए आज स्थिति कठिन हो गई है। ऐसी स्थिति में जहां पानी पड़ा हुआ है, उसका सही उपयोग किसी ने भी किया हो, वह राष्ट्र की प्रगति के लिए है और उसको आगे बढ़ाना चाहिए।

महोदय, मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता हूं लेकिन 1975 में जब मैं गुजरात में पहली दफा मिनिस्टर बना, तो मेरे पास एग्रीकल्चर और इरिगेशन डिपार्टमेंट था। मैंने सोचा कि मैं आज मिनिस्टर बना हूं, लेकिन मुझसे पहले जो मिनिस्टर थे, वे कांग्रेस के थे, वे आज भी हैं, उनका नाम

गोवर्धन भाई पटेल है। मैंने बड़े सम्मान से उनको अपने ऑफिस में बुलाया और उनसे पूछा कि गोवर्धन भाई, आप अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं हैं, मैं हूं, बदलाव आ गया है, लेकिन मैंने इसलिए आपको बुलाया है कि क्या कोई योजना आपके दिमाग में है जो आपने शुरू की है, यदि ऐसी कोई चीज हो तो मुझे बताइए, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। मेरा कहना यह है कि एन०डी०ए० सरकार ने किया है, इसलिए यू०पी०ए० सरकार उसको न करे, यह ठीक नहीं है। यदि कर दिया है तो बताइए कि एक साल में कितना आगे बढ़ाया है? अगर एक समिति बिखर गई है तो दूसरी समिति एपाइंट करो। एक-एक दिन उस पर काम करने की जरूरत है। इसलिए मैं जल संसाधन मंत्री जी से, मुंशी जी से निवेदन करता हूं कि इसको ऊपर गौर से विचार कीजिए और इस सदन में अपना ब्यौरा जल्दी से जल्दी पेश कीजिए जिससे क्षमता-कुक्षमता का वातावरण मिट जाए। ऐसे बहुत से प्रदेश हैं जहां हर 2 साल के बाद सूखा आता है, इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। वहां पानी पहुंचाना है, गांवों में किसानों के खेत में पानी पहुंचाना बड़ा कठिन काम है लेकिन इसे करना पड़ेगा। इसको करने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा कि एक हजार क्यूबिक मीटर से यदि पानी कम हो तो उसको वॉटर स्ट्रैस एरिया कहा जाता है। मैं कहूंगा कि हमारे गुजरात में वर्ष 2000 में सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में 274 क्यूबिक मीटर और कच्छ में 432 क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति हुई है। हम नर्मदा योजना, सरदार सरोवर डैम के लिए आग्रह कर रहे हैं, लेकिन इस डैम वर्क को बनाने में इतने रोड़े डाले गए, इतने रोड़े डाले गए, जितने किसी भी डैम के ऊपर रोड़े नहीं डाले गए। सूखा पीड़ितों के लिए यह पानी जाने वाला है, लेकिन रोड़े डालने वाले नहीं सोच रहे हैं, वे विस्थापितों की बात करते हैं। मैं प्रश्न उठाता हूं कि विस्थापितों की बात करनी चाहिए, लेकिन जो एक परमानेंट सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, वहां जो लोग रहते हैं, क्या वे विस्थापितों से कम जिन्दगी जीते हैं? वे भी विस्थापित हैं। एक का घर उजड़ जाता है, दूसरे का घर है ही नहीं। मेरा यह मानना है कि टिहरी डैम जैसा बहुद्देश्य वाला डैम, सरदार सरोवर डैम, नर्मदा डैम जैसा बहुद्देश्य वाला डैम, उसके ऊपर ही इतना आंदोलन क्यों होता है? क्या देश की प्रगति के लिए रोक लगाने की किसी की साजिश है? यदि हमारे पास भाखड़ा-नांगल नहीं होता तो आज भी हम राशन की लाइन में खड़े होते। देश में बड़े बांध बनें, भाखड़ा नांगल जैसे बांध बनें और आज राशन की लाइनें कम हो गई हैं। यह सिलसिला चालू रहना चाहिए---बड़े डैम बांधने का, मध्यम कक्षा के डैम बांधने का, छोटे डैम बांधने का, माइक्रो डैम बांधने का। मेरा कहना यह है कि बीच के समय में, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूरी राशि इस जल संसाधन डिपार्टमैंट को दी गई थी, आज बहुत कम राशि दी जा रही है। तो फिर हम पहुंचेंगे कैसे? मैंने उल्लेख किया वाटर ग्रिड का, नदियों को जोड़ने का, वहां से कितना पानी मिलने वाला है, जो 25 मिलियन हैक्टेयर ज्यादा पानी है, जो दूसरी जगह पर जाएगा, 25 लाख नहीं, 25 मिलियन हैक्टेयर एक अंदाज है, इससे जो सिंचाई होगी, उनमें से जो पानी जमीन में जाएगा, उससे पानी मिलने वाला है और दूसरा 10 मिलियन ज्यादा पानी है, पानी का उपयोग करना चाहिए। मैं कोई

आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि हम सबको मिल कर आगे बढ़ना पड़ेगा। यह पानी की आज की जो स्थिति है, उसमें बहुत कुछ करना बाकी है, यह हम लोग करें। आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए भी हम दे जाएं और आज की जो स्थिति है, उसमें भी सुधार लाएं। एक छोटी सी बात, गुजरात का समुद्री किनारा, पूरे देश के समुद्र का किनारा देख लीजिए। तो समुद्र के किनारे वाली जमीन में खारा पानी घुस जाता है और जमीन को बिगाड़ देता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, पूरे देश का जो समुद्र का किनारा है, उसमें से एक-तिहाई भाग गुजरात का है। इस कारण वहां पीने के पानी की बहुत कड़ी तकलीफ है। पिछले साल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर माननीय चिदम्बरम जी ने जो वक्तव्य दिया, उसमें उन्होंने आंध्र और चेन्नई के लिए 1 हजार करोड़ रुपए की राशि समुद्र के खारे पानी को मीठा कर लोगों को देने के लिए तय की। मैं कहना चाहता हूं कि उस तरह से गुजरात के लिए एक पैसा भी नहीं मिला। अब ऐसे और भी प्रदेश होंगे। आप खासकर चेन्नई के लिए दो, उसकी जरूरत है, मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन कहना चाहता हूं कि वहां गुजरात जैसे और क्षेत्रों के साथ यह अन्याय क्यों? उपसभाध्यक्ष महोदय, यह नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसी पानी की कमी को नहीं मिटाएंगे तो आने वाले दिनों में, पीएल 480 की तरह का अनाज और जो मदद हमें बाहर से मिलता थी और राशन की लाइनें बनती थीं, वे फिर से न आ जाएं, इसकी चिंता हमें करनी पड़ेगी।

महोदय, इस साल का जो आर्थिक सर्वेक्षण हमारे सामने रखा गया है, वह हमारी आंख खोलता है। उसमें कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर डेढ़ परसेंट है। अब अगर कृषि वृद्धि की दर यह रहेगी तो आने वाले दिनों में स्थिति क्या हो सकती है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। महोदय, भूख से पीड़ित जनता अपनी स्वाधीनता की रक्षा नहीं कर पाती। इसका महत्व बहुत है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर भारत को आर्थिक महा-सत्ता बनना है तो हमारा काम सिर्फ बड़े-बड़े उद्योगों से चलने वाला नहीं है। इसके लिए हमें करोड़ों की संख्या में देश में हर क्षेत्र में बिखरे हुए ग्रामीण किसान, मजदूर और छोटे किसानों के हाथों में हथियार देना चाहिए और वह हथियार है पानी और बिजली। फिर वह किसान, मजदूर पैदावारी कर लेगा, लेकिन उसे वह हथियार देने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। अगर इसके लिए हम कहें कि यह राज्यों का विषय है तो इस से बात बनने वाली नहीं है। हां, यह राज्यों का विषय जरूर है लेकिन हमें उनको ज्यादा-से-ज्यादा सहायता देनी पड़ेगी। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि AIBP (Accelerated Irrigation Benefit Programme) के तहत जो मदद राज्यों को मिलती है, उसमें त्वरित लाभ देते हुए एन॰डी॰ए॰ सरकार ने वर्ष 2004 की मंत्रिमंडल की एक बैठक में अच्छा निर्णय लिया। उन्होंने देश को इसके लिए दो क्षेत्रों में बांटा—एक पहाड़ी क्षेत्र व छोटे राज्य और उत्तर पूर्व के प्रदेश। उसमें बड़ी और मध्यम कद की योजना के लिए 90 प्रतिशत ग्रांट व 10 परसेंट लोन रखा गया और शेष पूरा देश सामान्य श्रेणी में। उसमें 30 परसेंट ग्रांट और 70 परसेंट लोन। मैं मुंशी जी को कहूंगा कि उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। इस देश का जो सूखाग्रस्त

क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र को इसमें पहली श्रेणी में शामिल करें, प्रदेश कोई भी हो। तो उसमें पहली श्रेणी में शामिल कर इस राज्य को 90 परसेंट ग्रांट और 10 परसेंट लोन मिलनी चाहिए। उसको 30-70 में मत डालिए। आदिवासी और कमजोर क्षेत्र हैं, उसको भी इस श्रेणी में डालें, तब जाकर सार्वजनिक सार्वत्रिक रूप से हममें से किसी को न लगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, यह परिस्थिति हम कर पाएंगे, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आर्टिफिशियल रिचार्ज भी करने की आवश्यकता है। मैं कहूंगा कि हमने गुजरात में यह किया है। गुजरात में हम लोगों ने प्रयोग नहीं, यह करके दिखाया है, लेकिन पानी समुद्र में बह जाता है, उसको कैसे रोका जाए? उसने जन-आन्दोलन का रूप ले लिया। 60 परसेंट राज्य सरकार की ओर से, 40 परसेंट प्रजा की, आर्थिक 100 परसेंट राशि मिल जाए और 40-60 परसेंट में, आपको ताज्जुब होगा कि दो साल में गुजरात में 44 हजार चैक डैम बना लिए गए। नदी के ऊपर छोटे-छोटे चैक डैम, पक्का डैम, छोटा डैम, उसको हम चैक डैम कहते हैं और 6000 गांवों के तालाब को desilting करवाए। किसके जरिए? सरकार, अकेली नहीं। हमने पंचायत के द्वारा एक बनी हुई समिति को पैसा दे दिया। लोगों ने इकट्ठे होकर अपने हाथों से, अपनी देख-भाल में, अपनी देख-रेख में यह डैम बनाया। यह डैम डेढ़ लाख का होता है, दो लाख का भी होता है, 44 हजार बना लिए। जैसे आन्दोलन होता है, ऐसे जन-आन्दोलन खड़ा हो गया। हमारे गुजरात के जो धर्म-पुरूष हैं, उन्होंने यह बात उठा ली। अपनी कथाओं में कहने लगे कि यह धर्म-कार्य है, यह करो। पानी का संचय धर्म-कार्य है। लोग लग गए। मेरा यह कहना है कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए तो लोग क्या नहीं कर सकते? एक एकड़ जमीन लेनी हो तो एक्वायर करने में कितनी तकलीफें होती हैं? गुजरात में हम लोगों ने पीने के पानी के लिए सात सौ किलो मीटर लम्बाई की, 4 x 4 मीटर की, पाईप लाईन 9 महीने में डाल दी। लोगों ने सहकार दिया। कोई कोर्ट में नहीं गये। कोई आदमी कोर्ट में नहीं गया। वातावरण बनाना चाहिए। ऐसा वातावरण बनाने से यह हो सकता है। मेरा अनुरोध है कि पूरे देश में यह वातावरण बनाया जाए पूरे भारत में अकालग्रस्त क्षेत्र बहुत हैं, वहां चैकडैम बनाएं, अनुश्रवण तालाब बनाएं और छोटे-मोटे दूसरे तरीके से तालाब बनाएं। इसमें लोगों का सहकार भी हो और लोगों के सहकार के जरिए हम आगे बढ़ें। इसमें सभी लोगों के साथ की बहुत आवश्यकता है, उनका सहकार एक महत्व रखता है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस सभागृह के जरिए मंत्री जी का और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो डैम से पानी छोड़ा जाता है और जो खेत में पहुंचता है, वह डैम का पानी हण्ड्रेड परसेंट खेत में पहुंचे। यह पानी किसके लिए छोड़ते हैं हम लोग? इसलिए कि वहां अनाज का पौधा लगाते हैं। लेकिन, जो अनाज का पौधा है, उसके लिए एक सीजन में कितना पानी चाहिए? हम जो टोटल पानी हण्ड्रेड परसेंट छोड़ते हैं, उसका फाइव परसेंट वहां पहुंचता है और 95 परसेंट पानी या तो जमीन में चला जाता है या बाहर निकल जाता है, इवोपेरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। सिर्फ पांच या छह परसेंट पानी ही पौधा लेता है। उनके लिए दूर-दूर से, 50 किलोमीटर दूर

से, 100 किलोमीटर दूर से पानी तो हम लाएंगे, लेकिन जब वह खेत में जाएगा तो वहां उसका ज्यादा बिगाड़ होता है। यदि कच्ची कैनाल है, तो कैनाल में बिगाड़ होता है। एक अंदाजा यह है कि 30 से 40 परसेंट पानी को बचाया जा सकता है, अगर इसके लिए कोई कार्य-योजना बनाई जाये और वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट इसके लिए राज्यों को प्रेरित करे, उनके लिए फंड अवेलेबल कराए। स्प्रिंकल के जरिए, ड्रिपएरीगेशन के जरिए यह सब हो सकता है। मैंने एक अंदाजे के लिए अपने टैक्नीकल आदमियों से पूछा कि भाई, एक हैक्टेयर जमीन में यदि सिंचाई करनी हो तो कुल मिलाकर कितना रुपया लगेगा, डैम बनेगा, कैनाल निकलेगी, नालियां निकलेंगी, सब कुछ होगा? तो मुझे बताया गया कि दो लाख रुपए। एक हैक्टेयर में इसके लिए दो लाख रुपया लगता है। एक डैम बन गया और कैनाल आगे बढ़ानी है तो एक हैक्टेयर पर पचास हजार रुपया लगता है और चैकडैम और अनुश्रवण तालाब का पानी जो जमीन में जाता है, कुएं से लोग पंपिंग करके निकाल लेते हैं, उसमें एक हैक्टेयर पर सिर्फ पच्चीस हजार रुपए लगता है। मैं समझता हूं कि यह भी हमको करना पड़ेगा। बड़े डैम, मध्यम डैम के लिए भी करना पड़ेगा और छोटे-छोटे डैमों, चैकडैम, जैसे छोटे जो माइक्रो डैम हैं, उनका जाल बिछाना पड़ेगा और तब जाकर पानी रुकेगा। मैंने जैसा कहा कि झोपड़-पट्टी में लोग जाने के लिए रोज-रोज लाखों की तादाद में लोग इधर आते हैं, उनको रोकना पड़ेगा क्योंकि शहरों में समस्या पैदा होती है। इसको यदि रोकना है तो पानी की उपलब्धि सर्वोच्च उपाय है। पानी अपने पास जितना है, उसको हम पूरी तरह से उपयोग में लाएं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं एक बहुत ही महत्व की योजना के बारे में बताना चाहूंगा। आपने गुजरात देखा होगा, वहां एक तरफ कच्छ है और दूसरी तरफ कंबात, जिसको गल्फ ऑफ केम्बे कहते हैं। इस गल्फ ऑफ केम्बे में नर्मदा का पानी आता है 'गल्फ ऑफ कैम्बे' में 'माही' नदी का पानी आता है, 'गल्फ ऑफ कैम्बे' में 'साबरमती' नदी का पानी आता है, यदि उसको बांधा जाए सिर्फ 28 किलोमीटर, मैंने नीदरलैंड में देखा है, वहां उन्होंने समुद्र को बांधा है, ऐसे ही यदि यहां बांधा जाए तो मीठा पानी मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 45 लाख एकड़ में सिंचाई होगी, इतना पानी मिल सकता है। उससे 6 हजार मैगावाट बिजली पैदा हो सकती है, वेव्स से, समुद्र की भरती वेव्स से। उससे सौराष्ट्र और गुजरात का जो डिस्टेंस है, वह 200 किलोमीटर कम हो जाता है। यह एक बड़ी योजना है इस कल्पतर योजना को केन्द्र सरकार उठाए, राज्य सरकार इतना पैसा खर्च नहीं कर पाएगी। वर्ष 2000 में उसका इस योजना पर अंदाजा था 54 हजार करोड़ का, वह योजना अभी तक विलंबित पड़ी है, उसका सारा अन्वेषण हो चुका है, लेकिन वह पड़ी है। इसे आप राष्ट्र के उपयोग में लाइए। इसको करने की आवश्यकता है।

अंत में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन अपने कुछ सुझाव आपको बताना चाहूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी) : केशुभाई जी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन आपके पास सिर्फ पांच मिनट का समय रह गया है।

श्री केशुभाई सवदास भाई पटेल: मैं केवल सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

1. ए॰आई॰बी॰पी॰ का लाभ सूखा प्रभावित क्षेत्र व डार्क जोन सेलिनिटी इन्ग्रेस, कमजोर वर्ग का क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र को विशेष श्रेणी में दाखिल करके 10-90 की श्रेणी में रखना चाहिए और इनके लिए आर्थिक प्रावधान केन्द्र सरकार को करना चाहिए।

2. ए॰आई॰बी॰पी॰ में छोटी योजना दाखिल करनी चाहिए। आज छोटी योजना ए॰आई॰बी॰पी॰ में नहीं है। छोटी योजना दाखिल करके सामान्य श्रेणी का लाभ उनको देना चाहिए। आज सिर्फ बड़ी और मध्यम योजना को ही लाभ मिलता है।

3. इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट, यह एनडीए की सरकार ने कार्यक्रम बनाया था, यूपीए सरकार ने इस कार्यक्रम को कितना आगे बढ़ाया है और आने वाले सालों में वे समयबद्ध इस बारे में क्या करना चाहते हैं, इसका ब्यौरा इस सभा के समक्ष रखा जाए।

4. ऐसे क्षेत्र, जहां आदिवासी और समाज के कमजोर वर्ग रहते हैं, वहां विशेष तौर पर योजनाओं का पता लगाया जाना चाहिए और पता लगाकर उन्हें लागू किया जाना चाहिए।

5. जल संसाधनों की देख-रेख तथा आधुनिकीकरण की अत्यंत आवश्यकता है।

6. अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 का पुन: अवलोकन किया जाना चाहिए तथा इसे सुधारकर जल विवादों पर जल प्राधिकरण द्वारा समय पर फैसला देने की आवश्यकता है।

7. चैक डैम, अनुश्रवण तालाब, छोटे और बड़े तालाब लाखों की संख्या में बनने चाहिए।

8. स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलना चाहिए।

9. गुजरात की कल्पसर जैसी बड़ी योजना को अकेले गुजरात सरकार कभी भी पूरा नहीं कर सकेगी। इस योजना में केन्द्र की खास मदद मिलनी चाहिए या केन्द्र को इस योजना का अमल अपने ऊपर लेना चाहिए।

10. पानी का सुचारू रूप से वितरण करने के लिए किसान कोआपरेटिव सोसाइटी, मैंने अपने प्रवचन में इसे डिटेल में नहीं लिया, लेकिन पानी का सुचारू रूप से वितरण करने के लिए किसान कोआपरेटिव सोसाइटी बड़े पैमाने पर बननी चाहिए।

इन सोसाइटीज़ के सुधार, उनके व्यवस्थापन के लिए फॉरमर्स पार्टिसिपेटरी इरिगेशन एक्ट, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि फॉरमर्स पार्टिसिपेटरी इरिगेशन एक्ट हर प्रदेश में बनाने के लिए, केन्द्र को राज्य सरकारों से आग्रह करके, इसके लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I am very happy to hear the speech made by my respected friend, Shri Keshubhai Patel. He said that the issue of water should not be politicised and no politics should be played. He also said that we are all one. I welcome it. This is a national problem. Every political party has to see that the problem of water scarcity is solved. We are all one in this. At the same time, he wanted to know from the Minister as to what is the speed of progress in regard to the solution to the problem of water scarcity. Of course, the Minister will reply to this point.

In our country, we have great rivers like the Ganga, the Brahmaputra, the Narmada, the Cauvery, the Krishna, the Godavari and so many other rivers. But here what happens is, in one part of the country people are suffering from floods and in other part of the country people are suffering from droughts. Ours is a vast nation with a very peculiar geological system. The law of nature is such that at some places the people are dying due to drought conditions and at some other places people are suffering miserably due to devastating floods. What is the solution to this problem? This issue is being debated for the last so many decades. We must remember that our country is totally dependent on agriculture. Crores of people living in the rural areas are dependent only on agriculture. If we compare ourselves with China, what is the position? China has accepted that so far as agriculture production is concerned, India is number one. We have so much of agriculture production in the country. China is giving top priority to agriculture production. They have been giving top priority to water resources, irrigation and dams along with industrialisation. In our country, when we are moving towards industrialisation, we must see that every acre of land is cultivated with water and water is made available.

So far as drinking water is concerned, today people are taking out underground water and using it as drinking water. There are a lot of deficiencies in the underground water. This water is not fit for drinking. Once we are able to solve this problem by having dams and canals throughout the country, we will be able to give best drinking water to the common people.

[THE VICE CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) in the Chair]

Why are we still lagging behind even after 57 years of Independence? What is the solution to this problem? Where do we stand? That is the most important thing to bear in mind. Today, when we are debating this

issue, it is not for fighting with each other, it is to exchange our views. The ultimate motivation of every citizen of the country and every Member of this House should be how to solve this problem.Even though we have been listening for decades that we must link the rivers from north to south, but it has not taken any shape. There is a scheme for linking 30 rivers. Perhaps, if you take up the scheme of linking 30 rivers all over India, Rs. 330 lakh crores are needed. Imagine, Sir, we need Rs. 330 lakh crores! Looking at this figure, everybody is afraid, and nobody gets anything. The present Government as well as the previous Government have done a lot of exercise on this. Now, the latest position is that they want to take up linking of six to eight rivers. One view is that the estimate would be Rs. 3,40,000 crores, and the other view is that it would be as high as Rs. 5,00,000crores. Anyway, even if we take an average of it, and say that if Rs. 4,00,000 crores are spent and we achieve the linking of say, eight rivers, in 10 years, then, the national water problem can be solved to some extent. For that, annually, you need about Rs. 40,000 crores. It may sound to be a big figure. But there are so many agencies which are willing to assist us in this. People are prepared to invest and Build, Operate and Transfer. Similarly, in irrigation projects as well, there are countries in the world and entrepreneurs in the nation who are prepared to come and undertake to Build, Operate and Transfer. Similarly, international organisations like the World Bank and the Asian Development Bank—probably, India is the only country which is able to take maximum benefit from the World Bank—are also eager to provide funds. But the fact is that we are not really able to take maximum benefit because of red tapism, lack of communication and various other delays. Therefore, we can solve the problem of funding by providing Rs. 40,000 crores every year in our national Budget. Sir, today, the position is that the commercial banks have surplus funds. They are coming forward to lend money with nil interest. Besides international organistions, we also have other organisations like the LIC, GIC, which are also prepared, on the guarantee of the Government, to provide financial assistance. Therefore, I am bringing to the notice of the hon. Minister, Dasmunshiji, that he must work out with the Finance Ministry and have revision of the Plan Outlay in the national Budget. A very small amount of money has been allocated for the Ministry of Water Resources in the Budget, and this sends an absolutely wrong message to everybody. How can we then solve the problem?

Then, Sir, besides the Central Government, it is the duty and responsibility of the State Governments also to take suitable measures to solve this problem. Every State has got its own policy. Some States want mass industrialisation; some States want to concentrate on agriculture. Now, for example, you take the case of Andhra Pradesh. The present Government is giving its topmost priority to agriculture sector. It has been found that ultimately it is the farmers and success in agricultural productivity which would go a long way in solving our problems. So, besides our interests in massive industrialisation, encouraging modern technologies, software and everything, we do want to concentrate amply in irrigation system. For instance, in Andhra Pradesh, we have got 2,840 TMCs of water—1 TMC is equivalent to 10,000 acres—allocated by that system. Besides this, 2000 TMCs of water, which is surplus, go waste in the form of floods in rains, which means we have got 4,840 TMCs of water which is available. But we are hardly using 1,700 TMCs of water in the present system. I am very happy that at least Andhra Pradesh has become a bold State by coming out with a Plan that it would be spending Rs. 46,000 crores in five years under this project. Of course, some people have their own doubts as to how it is possible. Yes; it is true. For instance, they are investing Rs. 46,000 crores, and if they are able to spend on 26 irrigation projects, then, in five years, every acre of land in Andhra Pradesh would have sufficient water available for it.

Water will be available everywhere in Andhra Pradesh in the next five years. As of today, water for irrigation is available only for 17 lakh acres of land in Andhra Pradesh. We are going to make it available for a minimum of 65 to 80 lakh acres of land in the next five years.

So far as the Budget allocation is concerned, the UPA Government is totally committed to irrigation and agricultural production which, we feel, has a major role to play in the development of our economy and in helping our farmers. The hon. Prime Minister gave full support when he visited the State of Andhra Pradesh. He said, "The Centre will give any amount you want for increasing the agricultural productivity to help the nation and, particularly, the State of Andhra Pradesh". Similarly, the UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi, is also prepared to give full support, as the Common Minimum Programme is committed to provide irrigation facility to one crore acres of land in these five years. I will give you a small example of the provision for irrigation in the 2004-05 Budget, as compared to what was

given by the previous Government. Perhaps, there were other good things. I am not criticising. But I am giving only factual information. I was told that Rs. 1640 crores were allotted for irrigation. When our Government came in, it gave Rs. 3440 crores in 2004-05. In the present Budget, our Chief Minister has provided Rs. 7400 crores. in the next Budget, he is proposing to give Rs. 10,000 crores. So, where there is a will there is a way. We are going to prove that it is possible to make available Rs. 7400 crores by raising money through institutions like LIC, GIC, the Austrian Government, ADB and the World Bank. These institutions are prepared to give once they are convinced that every rupee is going to be spent for the purpose, and not just for image-making, and once they know that it is a long-term policy.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: What is the amount that you have got from the Austrian Government? (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Please do not talk to him. (*Interruptions*) Mr. Reddy, you look to this side. (*Interruptions*) Let him speak.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, Andhra Pradesh has proved to be a model State. The Common Minimum Programme is committed to provide irrigation to one crore acres of land. The State of Andhra Pradesh has a very, very ambitious programme to provide irrigation facility in 65 lakh acres of land. It is possible and it will be done. No force will be allowed to stop it. God is there to see to it that it is done. (*Interruptions*) Money will come. There are ways. The World Bank is ready; ADB is ready; LIC is ready; GIC is ready; Commercial Banks are ready; the Austrian Government is ready. Everybody is ready. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Will you please keep quiet? Let him speak.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: He is referring to me?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): He is talking to you because you stand up. Don't stand up. Please sit down.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I request my dear friend, the dynamic...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): You have only two minutes. If you talk to him, you will lose your time.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, what we have to do now is that we have to eradicate red-tapism. I will give you a small example. There are so many projects in Andhra Pradesh. You have the Bhupathiparlem Project; the report was sent to the Ministry of Tribal Affairs for clearance. It is pending. Again, in regard to the Gundlakamma Project, the rehabilitation and resettlement proposal was sent to the Ministry of Tribal Affairs. Similarly, in the case of the Lendi Project, an Inter-State Project between Government of Maharashtra and Andhra Pradesh, as per information available, the DPR was submitted to CWC in 2001. Today, we are in 2005. Nothing has happened. Then, in the case of Modikuntavagu project, the DPR was sent to CWC in 2004. It is pending for CWC clearance. In the case of Pulichintala Project, the local office of Archaeological Survey of India has completed the inspection of temples and submitted the report to the DG, ASI, New Delhi on 10.2.05. The NoC is awaited. (*Time Bell*) I am concluding, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): What do you want?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: I want to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): How much more time will you take?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, Keshubhai Patelji spoke for one hour. I will speak for at least twenty minutes. From the BJP side, he spoke for one hour.

Sir, the hon. Member from the BJP spoke for one hour. I would be allowed to speak, at least, for half-an-hour.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Mr. Reddy, you must understand that there is no comparison between how much he spoke and how much you are going to speak. (*Interruptions*) Listen to me. From their side, there was one speaker. But, from you side, there are four speakers. So, you cannot have all the time. (*Interruptions*) If you want to have it, I have no problem; the other speakers from your party will lose it.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, as I am speaking on a very important subject, I am speaking on behalf of you and everybody. Another important thing is, I am happy to state that the study of the feasibility of the waterways India and Nepal have started. The joint review of the Sapta Koshi and Sun

Koshi multi-purpose projects which has been accepted by New Delhi is likely to be considered by the Indian Government. I would like to know from the hon. Minsiter by which time you are going to do it. I would also like to know from the hon. Minister about the outcome of the Indo-Nepal waterways feasibility study undertaken and by what time it will be finally agreed? I would also like to know whether the Planning Commission and the Water Resources Ministry have urged the Centre to fully fund select major irrigation projects to ensure speedier completion. Sir, actually, here, I would like to say that the Centre must come forward, select some big irrigation projects at national level and complete them. But, till today, nothing is happening in this regard. In fact, the Ministry of Water Resources should be strengthened. The Finance Ministry must allocate more money to the Ministry of Water Resoruces for completion of these projects. Actually, as on today, the Central Government is spending its time in giving clearance to various projects and in solving inter-State water disputes. The major irrigation projects are not getting much attention of the Central Government.

Sir, I would like to know from the hon. Minister whether it has been recommended by the Planning Commission in the mid-term appraisal, which is under preparation, to the Water Resources Ministry to fully fund select major irrigation projects to ensure their speedier completion; if so, whether there are about 160 major irrigation projects, which include construction of dams and reservoirs under implementation, etc; if so, whether these projects include projects that were started prior to the Fifth Plan period. I would also like to know from the hon. Minister whether the Ministry is of the view that about 15 large projects which could benefit about one lakh hectare or more than one State should be fully funded by the Centre. In this connection, actually, I have been requesting the hon. Prime Minister, the Finance Minister and, of course, through you, the hon. Water Resources Minister that they must take up one major project in each State. Then, they must provide funds for these projects. Funds can be arranged from bodies like the World Bank, ADB and various other financial institutions. All the parties are going to support it. There would not be any difference on this issue.

Sir, the State Governments are making efforts to complete these projects. Apart from the financial constraint, the major problem which is affecting these projects is red-tapism in clearing these projects. A lot of time is taken in clearing these projects. There are inter-State water disputes

between various States. I request the hon. Minsiter to solve these problems quickly. For example, there are disputes like the Cauvery water dispute between Karnataka and Tamil Nadu and the Krishna water dispute between Andhra Pradesh and Karnataka. Similarly, in the North India there are various water disptues. There are disptues about various rivers including the river Brahmaputra. These water disptues have been dragging on for decades. The time has come to solve these disputes. There should be one-to-one discussion between the disputing States to solve these disputes quickly. They must solve these problems in a conscientious way and in a judicious way. It should be done in the interest of the people of India.

Sir, in conclusion, I would like to say this. A day is going to come when even though you will be able to conquer the hunger of the people in India, shortage of water is going to be a serious problem. It is going to create social and political problems for our country. I find that still we are not giving much importance to it. They are talking about the National Water Development Agency, Task Force and so many other things. The moment it is said that they require a lot of investment, they are afraid of it. Now, the time has to come to overcome all these problems. If a system is built up, we will be able to raise money for it. The Government must commit itself to inter-linking of rivers. It is not possible to inter-link 20 or 30 rivers in one go. Take two rivers for inter-linking immediately.

Take up a leading example. Take up a project at the Central level, concentrate on that and provide funds to it from various sources and make it an example. Whenever any State is serious to take up projects, if they send proposals for environmental clearance, forest clearance, tribal clearance, design clearance, there should be a time-limit and see to it that the Ministry of Water Resoruces has full powers. It must see to it that it pulls up the colleague Ministries also and see to it that clearances are given well in time.

Lastly, the UPA Government is totally committed to give a top priority to the water system. They are going to have a national policy on water distribution. Our hon. Prime Minister is planning to have a conference of Chief Ministers, very shortly, in Delhi and discuss for adiscussion with them. Before that, I was told, our Minister has been requested to have a one-to-one discussion with the Chief Minsiters to understand their problems. And afterwards, there will be the Chief Ministers' conference. I am very

happy that this time a very good subject has been taken up for discussion here.

I call upon all he political parties to be together and make लोकोत्तर संघटन a prosperous one. Let us make this nation as a matchless, spectacular and unparalieled one in the world Without agriculture and using irrigation potentiality, thereby farmers' happiness, you can't think of prosperity of this nation.

Therefore, I call upon our Government to see to it that top priority is given to water management. I once again compliment, personally, the Andhra Pradesh Government on their move and it should be followed by other States too. If every State follows that system—having an ambitious proposal of giving water for lakhs of acres in five years—the nation is going to be much more prosperous. Thank you all.

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिमी बंगाल): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री के कार्यकरण पर चर्चा करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि जल संसाधन से जुड़े हुए जो दो विशिष्ट मंत्रालय हैं, जिन दोनों के कोऑर्डिनेशन और सहयोग से ही इस समस्या से हमें मुक्ति मिल सकेगी, इन दोनों मंत्रालयों के मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। इस चर्चा से पहले यहां एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट दी गई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि संसद की एथिक्स का यह बहुत अच्छा उदाहरण है कि यहां दोनों मंत्रालयों के मंत्री उपस्थित हैं।

महोदय, मैं यू॰ पी॰ ए॰ सरकार के सत्ता में आने के बाद, जो उन्होंने अपनी प्राइयॉरिटीज़ निर्धारित की हैं, उसके एक नोट पर नज़र डाल रही थी, तो मैंने देखा कि जल संसाधन से जुड़ी हुई जिन प्राइयॉरिटीज़ को, जिन प्राथमिकताओं को सामने रखा गया है, उनको मैं क्वोट करना चाहूंगी, वे हैं— Task Force Report; recommendation and action taken thereon; AIBP position; allocation for AIBP in this year's Budget; command area development programme; river linking programme; inter-State water dispute; river erosion; coastal erosion management; and, water bodies restoration. ये जो समस्याएं आम तौर पर आती रही हैं, सबको अपनी प्राथमिकता में सरकार ने लिया है, उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगी। माननीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी यहा हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक कहावत से मैं अपनी बात शुरु करना चाहूंगी। वहां एक जनकवि हैं "भाग", जिन्होंने अपनी कहावतों में जीवन को उकेरने की चेष्टा की है। एक कहावत हैं—"उत्तम खेती मध्यम बान, निखत चाकरी भीख निदान" अर्थात् उत्तम व्यवसाय है खेती, ऐसे ही मध्यम है वाणिज्य, निषिद्ध है

नौकरी और मजबूरी है भीख मांगना। जल की कमी और जल के अधिक्य से हमारे देश का किसान अपने इस उत्तम पेशे को छोड़कर मजबूरी के पेशे, भीख मांगने के पेशे पर आ जाता है और भुखमरी का शिकार होता है। इसलिए जल को बचाना, जल का संरक्षण, जल का सदुपयोग जीवन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है।

माननीय केशुभाई जी ने अपने मूल्यवान वक्तव्य में, भाषण में कहा कि जल को लेकर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी-कभी ऐसा मौका आता है कि जब एक प्रदेश के लोग बाढ़ से पीड़ित होकर त्राहि-त्राहि कर रहे होते हैं, तो एक राजनीतिक दल फब्तियां कसता है कि यह मैन-मेड फ्लड है। तब ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहिए, यह प्रश्न बार-बार हमारे मन में उठता है।

सचमुच जल को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जल जिंदगी है और जल को बचाकर ही हम अपने देश के लोगों के जीवन को बचा सकते हैं, भविष्य को बचा सकते हैं। हमारे पुराने शास्त्रों से लेकर आज तक, यह बात हर जगह कही गई है, जल जीवन है, जल जीवन का पर्याय है, जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। जल मनुष्य के लिए प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है। दुनिया की सभ्यताएं, नगर, गांव, कस्बे, नदियों के किनारे बसे, नदियों के प्रेम से पाले गए और नदियों के प्रकोप से उजड़े भी। अगर हम भारतीय सभ्यता के प्रस्फुटन पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि इस महाद्वीप की नदियों के आस-पास के मैदानों, खासतौर से उत्तर में गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र तथा दक्षिण में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के मैदानों में विकसित होने वाली उच्चकोटि की खेती के कारण ही सभ्यता विकसित हुई। किन्तु आज सारी दुनिया में पानी की बढ़ती मांग और बढ़ते दोहन ने दुनिया की कुछ प्रमुख नदियों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान के प्रमुख फ्रैंक रिज-बर्मन ने सन् 2001 में ही स्टॉकहोम में जो विश्व सम्मेलन हुआ, उसमें सूचना दी कि सन् 2025 में दुनिया की एक तिहाई आबादी को पानी की भयंकर परेशानी से जूझना पड़ेगा। एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, पानी का उपयोग भी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, जिनमें साल भर जल रहता है, जिन्हें सदानीरा नदियां कहते हैं, आज दूषित जल के नालों जैसी हो गई हैं। इस संदर्भ में पानी की किल्लत बढ़ने और अलग-अलग देशों के टकराव की स्थितियां बनने की आशंका भी गलत नहीं लगती। इस बढ़ते जल संकट के परिप्रेक्ष्य में अलग-अलग देशों के मंत्रालयों में, जल संसाधन मंत्रालय अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है और उसकी भूमिका भी बड़ी अहम हो गई है। भारत सरकार का जल संसाधन मंत्रालय देश के जल संसाधनों के विकास और विनियमन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अनेक कार्य हैं, जिनमें मुख्य है, राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल का विकास, संरक्षण और प्रबंधन, सिंचाई नीति गठन, भूजल संसाधनों का

4-00 P.M.

संरक्षण, सूखा रोधन, बाढ़ नियंत्रण बांध सुरक्षा, जल जमाव और जल कटाव की समस्याओं का निराकरण। ऐसे ही अन्तर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों का विनियमन और विकास है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं और करीब 17 संगठन हैं, जो जल संसाधन मंत्रालय को मदद देने वाले हैं, अनेक योजनाएं हैं कागजों पर बहुत कुछ है। इतना कुछ है, फिर भी यदि मैं कबीर का याद करूं तो मैं कहना चाहूंगी कि 'जल बीच मीन प्यासी, मोहे सुन आवत हांसी।' इतना जल है, बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी देश में कभी जल की समस्या है और कभी जल का अभाव है। इस मंत्रालय ने पहली बार राष्ट्रीय जल नीति सन् 1987 में अपनाई थी और इसको 1 अप्रैल, 2002 को संशोधित किया गया तथा नई राष्ट्रीय जल नीति घोषित की गई। हमने 2003 को स्वच्छ जल के [illegible] में मना लिया है, लेकिन आज भी हमारी जनता कहीं बाढ़ में डूब रही है, कहीं सूखे में जल रही है, कहीं नदी तट क्षरण से, गांव के गांव नदी के गर्भ में विलीन होते जा रहे हैं, तो कहीं अन्य देशों से आई मेहमान नदियां, जल का जलजला-उपहार लेकर आती हैं और अपार धन, जन की हानि को निमंत्रण दे जाती हैं। कहीं पर लोग आर्सेनिक प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं तो कहीं अंतर्राज्यीय जल विवाद के चलते, जो हर रोज जल की जरूरत है, वह भी पूरी नहीं हो पाती। आखिर क्या सबब है कि योजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। उनके लिए किसी को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाता? मैं गत वर्ष की संसदीय समिति की सिफारिशों पर नजर डाल रही थी। मैं उसी को उद्धृत करना चाहूंगी, 'समिति यह नोट करके खेद प्रकट करती है कि दसवीं योजना के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित 6651.41 करोड़ रुपए के परिव्यय के स्थान पर, योजना आयोग ने केवल 3600 करोड़ रुपए परिव्यय की स्वीकृति दी, जो कि प्रस्तावित परिव्यय का लगभग 60 परसेंट बैठता है।' इस बार की रिपोर्ट जो आज ही संसद के पटल पर रखी गई है, उसमें भी इसी तरह की बात है, मंत्रालय जो बजट देता है, उस पूरे बजट को फाइनेंश कमीशन, योजना आयोग स्वीकृति नहीं देता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत को बचाने का अर्थ है अपनी नदियों, झीलों, तालाबों, जोहड़ों, पोखरों, नहरों, कुओं, बंबों, चश्मों, झरनों और बरसाती नदी, नालों, बावड़ियों को बचाना, क्योंकि भारतीयता को जीवित रखने का आधार ये ही हैं। मैं कहना चाहूंगी कि जैसे बोतलबंद पानी को खाद्य पदार्थ मानकर उसके मानक तय किए गए हैं, वैसे ही सामान्य पानी को स्वास्थ्यप्रद बनाने के भी मानक तय किए जाएं। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी झोपड़-पट्टियों तक शुद्ध पेय जल को सुरक्षित किया जाए, पर इसकी आड़ लेकर पानी के व्यापारीकरण का निजी बाजार न खोला जाए। अभी साल भर पहले बस्तर की जगदीश नदी के पानी का जब निजीकरण किया गया तब जबर्दस्त हंगामा हुआ। इससे पहले भी जल स्रोतों पर निजी अधिकार के मामले आते रहे हैं। गंगोत्री और गोमुख के पानी पर निजी कंपनी के अधिकार का मामला भी सामने आया था। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि इस तरह जल को प्रोडक्ट न बनाया जाए। मैं थोड़ा-सा पूर्व की सरकार के

कार्यक्रम पर भी कुछ कहना चाहूंगी। एन॰डी॰ए॰ सरकार के दिमाग में बहुत सारे फितूर थे, जिनमें से एक था नदियों को जोड़ना। एक ओर तो उस समय बजट में कटौती की गई थी, दूसरी ओर 60 करोड़, 56 लाख की लागत वाली यह योजना डंके की चोट पर प्रस्तावित की थी। नदी जोड़ की यह भयानक पहल किस प्रकार देश के वातावरण को बदल देती और किस तरह इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ देती, यह बिना समझे प्रयोग किया गया था। पूर्व मंत्री ने भावुक बयान देकर छद्म राष्ट्रीयता का जाल भी बिछा दिया था। यह सिर्फ पानी की कमी को दूर करने की योजना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय नव निर्माण का कार्यक्रम है, यह कहते हुए उन्होंने यह कहा था कि यह देश की तसवीर और तकदीर को भी बदल देगी, लेकिन बिना किसी प्रकार का सर्वेक्षण कराए सरकार ने यह जो कल्पना की थी, वह देश के लिए बड़ी ही समस्यामूलक होती। मैं माननीय जल संसाधन मंत्री जी से....(व्यवधान)...

श्री एकनाथ के॰ ठाकुर: जो सदन में नहीं हैं, उन पर आरोप नहीं करना चाहिए।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: सॉरी, मुझे उनका नाम नहीं लेना चाहिए था। मैं माननीय जल संसाधन मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अब अगर वे इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को प्रश्रय देना चाह रहे हैं तो इसे बहुत सोच-समझकर आगे बढ़ाएं। जैसाकि मैंने रिपोर्ट में पढ़ा है कि उन्होंने विशेषज्ञों का दल निर्मित किया है और उन विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने के बाद ही यह काम शुरू किया जाए। ''नदी जोड़ो परियोजना'' से पहला खतरा पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का था। जैव विविधता और वानस्पतिक भूगोल भी अस्त-व्यस्त हो सकता है, इसलिए इन विशेष क्षेत्रों से विशेषज्ञों को लेकर जो टीम बनाई जाए, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही यह काम शुरू होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगी कि किसी भी कीमत पर आपसी बातचीत और विवाद को निबटाने की मशीनरी बनानी चाहिए, जिससे देश के पर्यावरण कर रक्षा के साथ सभी के लिए जल सुनिश्चित कराया जाए। ''नदी जोड़ो योजना'' का एक बड़ा खतरा यह भी था कि कुदरती पानी भी सरकारी संपत्ति बन जाता और नैसर्गिक संपदा, पानी के निजीकरण और व्यापारीकरण की संभावनाएं बहुत बढ़ जातीं। इस योजना का कई राज्यों ने विरोध भी किया था। मैं कह चुकी हूं कि जो टास्क फोर्स सरकार अब बनाए, उसमें इस पर विशेष ध्यान दे। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ दिन पहले भू-जल स्तर विषय पर एक सेमिनार में भाग लेने के लिए वियतनाम गई थी। वहां इस्राइल के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके यहां भूमिगत तालाबों के उपयोग की तकनीक विकसित की गई है, जिससे भू-जल स्तर के सुधरने की प्रचुर संभावनाएं हैं। वे शहर के गंदे पानी को समुद्र में नहीं बहाते, उसे खुले में छोड़ देते हैं, रेगिस्तान में फैला देते हैं और फिर सौ दिन के बाद एक टनल के माध्यम से उस पानी को बाहर निकालते हैं। यह जो रीसाइक्लिंग किया हुआ पानी होता है, यह शुद्ध जल के रूप में सामने आता है। मैं इस संबंध में वाटर हार्वेस्टिंग विकल्प पर भी मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगी, जिससे कि जो पानी बरसता है, उसे संरक्षित किया जाए और उसे पेय जल के रूप में काम में लाया जाए। उपसभाध्यक्ष

महोदय, बंगाल की एक बहुत बड़ी समस्या नदी कटाव है, जिसकी त्रिभीषिका के शिकार हर साल हजारों लोग होते हैं। धन-जल की इस हानि से बचने का उपाय तलाशने के लिए हमने कई बार संसद में, संसद के बाहर प्रश्न उठाया है।

यूपीए सरकार ने उसे अपनी प्राथमिकता में रखा है और अधिक धन आबंटन के साथ राज्य की विविध योजनाओं को केन्द्रीय मदद देना स्वीकार किया है। उसने तट-क्षरण एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय जल योजना घोषित करने की भी बात की है। मैं इस पहल की सराहना करना चाहूंगी।

महोदय, मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। हमारे यहां आर्सेनिक की समस्या से जूझने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है। भूटान सरकार के सहयोग से नार्थ बंगाल में आनेवाली बाढ़ को रोकने के लिए भी मैं एक प्रकल्प बनाए जाने की मांग करती हूं। महोदय, हमारे प्रदेश की एक और बहुत बड़ी समस्या नदियों में गाद इकट्ठे हो जाने की है। उसके बारे में भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

अंत में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी जिसके तहत एक ऐसी वैज्ञानिक जल प्रबंधन प्रणाली लागू की जाए जो हमारी भूमि और जल स्रोतों को प्रभावी ढंग से संयोजित करे। इसके लिए आवश्यक है कि (1) निर्माणाधीन तमाम सिंचाई परियोजनाओं को सरकार द्वारा आवश्यक धन मुहैय्या कराकर युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए, (2) वर्तमान सिंचाई योजनाओं का रख-रखाव उचित तरीके से हो और उसे सही तरीके से चलाया जाए, (3) सभी स्तरों पर पंचायतों के द्वारा आम लोगों की सक्रिय भागीदारी से जल संचय और जल संरक्षण के विकास के लिए तमाम कदम उठाए जाएं ताकि जमीन के ऊपर के और वर्षा के पानी का अधिकतम इस्तेमाल हो सके, (4) बाढ़ और सूखा नियंत्रण के लिए तुरंत उपयुक्त कदम उठाए जाएं, (5) भू-क्षरण, कटाव आदि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हुए भू-संरक्षण योजनाओं को खासकर जल ग्रहण और सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्रों में लागू किया जाए, (6) वन विभाग की बंजर और बेकार जमीन को विकसित कर सामाजिक वन-सृजन अभियान शुरू किया जाए, (7) छोटी, मंझोली और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अनुपात को उचित ढंग से निर्धारित किया जाए, (8) भू-गर्भीय क्षरण को रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं और मेरा अंतिम सुझाव यह है कि हमारे देश के पूर्वी प्रदेशों में जल प्राचुर्य है, इसलिए वहां के जल को विशेष रूप से संरक्षित कर उसे वन सृजन के काम में लगाया जाए।

अंत में, मैं इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन करूंगी और अपनी बात इस उम्मीद के साथ समाप्त करूंगी कि आजादी की अर्ध-सदी बीत जाने के बाद अब हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमारे देश की जनता कभी जल में डूबने, जल में बहने और कभी जल की बूंद के लिए तरसने को मजबूर न हो। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जय प्रकाश नारायण यादव।

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): महोदय, आज सदन में जल संसाधन विभाग पर विचार-विमर्श हो रहा है और माननीय सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव यहां दिए हैं। यह बहस आगे भी जारी रहेगी और तत्पश्चात् विभाग के माननीय मंत्री जी द्वारा विस्तार से जवाब दिया जाएगा।

महोदय, माननीय केशुभाई सवदास भाई पटेल साहब ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने पीने के पानी और सिंचाई के बेहतर प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की। महोदय, जल जीवन से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। महोदय, रहीम जी का एक दोहा है–

रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,

पानी गए न ऊबरे, मोती मानस चून।

महोदय, पानी का मानव जीवन में बहुत महत्व है। जैसे मछली बिना पानी के नहीं जी सकती, वैसे ही इंसान भी बिना पानी के नहीं जी सकता है। प्रकृति ने हमें पानी दिया है और इस पानी का बेहतर प्रबंधन कर के हम देश का चतुर्दिक विकास करें, खेतों तक पानी पहुंचाएं, सिंचाई का बेहतर प्रबंधन करें और पेयजल का सुव्यवस्थित प्रबंधन करें ताकि सूखे के समय पानी का संकट उत्पन्न न हो और न पानी के अभाव में खेती मारी जा सके।

महोदय, आज दुनिया में पानी के लिए बड़ी आपा-धापी और हलचल मची हुई है। जितना सोना-चांदी के लिए नहीं, उतना पानी के लिए आज सम्पूर्ण देश में आपा-धापी मच रही है। सम्पूर्ण देश में पानी की सुव्यवस्थित व्यवस्था और प्रबंधन करें, इसके लिए यही बेहतर उपाय है। जब से यू॰पी॰ए॰ गवर्नमेंट आई है, कई महत्वपूर्ण योजनाओं को सामने लाने का काम किया है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत भी कई योजनाएं ली गई हैं। मैं सबसे पहले इस बात को दर्शाना चाहूंगा कि जहां ए॰आई॰बी॰पी॰ योजना के तहत उन राज्यों को, जिनके पास सीमित संसाधन हैं और अपनी क्षमता के आधार पर अधूरे कार्य को पूरा नहीं कर पाए, उसके लिए 1996-97 में ए॰आई॰बी॰पी॰ कार्यक्रम बनाया गया। उसके तहत फास्ट ट्रैक कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें 70 परसेंट और 30 परसेंट के रेश्यो से राशि देने की व्यवस्था है, साथ-साथ विशेष श्रेणी में 10 और 90 के आधार पर राशि देने की व्यवस्था है। इसको हमारे मंत्रालय ने बड़ी मजबूती के साथ लिया है क्योंकि टाईम-बाउंड तरीके से योजनाएं हमें पूरी करनी हैं। आज जो हमारा ए॰आई॰बी॰पी॰ कार्यक्रम है, इसके तहत वर्ष 2004-2005 के दौरान विभिन्न वृहत्, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1800 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय की तुलना में सीले ने 2881.21 करोड़ रुपए की राशि ऋण घटक के रूप में

और 780.13 करोड़ रुपए की राशि अनुदान घटक के रूप में जारी की है। इस कार्यक्रम के तहत 184 वृहत्, मध्यम और 4169 लघु सिंचाई स्कीमों के लिए अब तक 17537.57 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं और इस योजना के तहत इन कामों को लेकर हम इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे ...(व्यवधान)...

SHRI JAIRAM RAMESH (Andhra Pradesh): Sir, the debate ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): One minute...(*Interruptions*)... What is your problem?... एक मिनट।

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the debate still going on, or, the Minister is replying now? I think other Members also want to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): No, no. The Minister is not replying. He is not replying. He is only intervening. The reply will come from the Cabinet Minister...(*Interruptions*)...

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: इसके साथ-साथ बाढ़ प्रबंधन और कटाव निरोधक कमान क्षेत्र विकास ...(व्यवधान)...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, there is a confusion in the House whether ...(*Interruptions*)...

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: जल प्रबंधन के कार्यक्रम, जल निकायों की मरम्मती, नवीकरण ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): There is always a standard provision for intervening... (*Interruptions*)...It is nothing new ...(*Interruptions*)...

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: विस्तार योजना के तहत कार्य किए गए हैं। वर्षा-जल संचयन, भू-जल का कृत्रिम प्रवर्द्धन और भू-जल स्तर में गिरावट, कई ऐसे सवाल हैं, जिन पर माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। महोदय, सबसे पहले यू०पी०ए० गवर्नमेंट जब सत्ता में आई तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया गया कि जो लगातार नेपाल में हाई डैम बनाओ, हाई डैम बनाओ, नेपाल में हाई डैम बनाने के लिए चर्चा होती रही, लेकिन कभी उसके लिए नेपाल सरकार से लेटर ऑफ एक्सचेंज नहीं हुआ, उसका कोई समझौता नहीं हुआ, परन्तु यू०पी०ए० गवर्नमेंट बनने के बाद दो महीने के अन्दर, यह देश के लिए खुशखबरी है और जहां हम चर्चा कर रहे हैं सिंचाई संसाधनों के लिए कि कैसे हम खेतों तक पानी पहुंचाएं, हम कैसे इसका बेहतर प्रबंधन करें, वहां आज नेपाल

में हाई डैम बनाने के लिए भारत सरकार और नेपाल में वार्ता हुई। वार्ता का नतीजा निकला कि एक्सचेंज ऑफ लेटर हुआ। एक्सचेंज ऑफ लेटर ही नहीं हुआ, इस वार्ता का इम्मीडिएट नतीजा निकला कि नेपाल में हाई डैम बनाने के लिए सप्त कोसी पर और सन कोसी पर उसका डी॰ पी॰ आर॰ बनाने के लिए समझौता हुआ और 30 करोड़ रूपए विभाग से मार्क किए गए, राशि स्वीकृत की गई, नेपाल में कार्यालय खुले और आज नेपाल में पांच जगह कार्यालय खोले गए हैं। डी॰ पी॰ आर॰ बन रहा है। यह कभी नहीं हुआ था। जब तक हम सप्त कोसी और सन कोसी पर हाई डैम नहीं बनाएंगे, तब तक बाढ़ से उत्तर बिहार की जो बर्बादी हो रही है, उसके सटे राज्यों की जो बर्बादी हो रही है, उस बर्बादी से हम नहीं बचा सकते हैं और आज उसके लिए डी॰ पी॰ आर॰ बन रहा है। उसके साथ-साथ कमला और बागमती पर भी डी॰ पी॰ आर॰ बने। आज जो सप्त कोसी को देख रहा है, वही उसे देखने का काम करेगा, यह यू॰ पी॰ ए॰ गवर्नमेंट की एक विक्टरी है। और हम दूरगामी लक्ष्य बनाएंगे। नेपाल का यह हाई-डैम बनाएंगे, जिससे बिजली भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, बाढ़ का प्रबंधन होगा, सूखे से बचाव होगा। उत्तर बिहार में पिछले साल जो बर्बादी और तबाही हुई, जिसमें जान-माल की हानि हुई, काफी बर्बादी हुई, पूरा जलमग्न हो गया इलाका-इलाका और जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एअर सर्वे किया था और सर्वे करने के बाद उन्होंने जो कुछ देखा, वहां की तबाही और बर्बादी, उसको देखने के बाद यह कहा कि टास्क-फोर्स बनाना है और उस आधार पर टास्क-फोर्स बनाया गया। ...(**व्यवधान**)...

श्री एकनाथ के॰ ठाकुर: सर, यह क्या हो रहा है?

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): एक मिनट ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): सर, जो वे लोग बोलते हैं, वह आप भी, मंत्री जी भी बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): एक मिनट, भंडारी जी। एकनाथ जी, आपकी प्रोब्लम क्या है?

SHRI EKANATH K. THAKUR: Sir, water is the most important issue. We are here to hear the Minister's reply. Now, another Minister in the same Cabinet, is he entitled to ...(*Interrupitions*)... Many Members are still to speak ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Will you please wait for a second? You know the procedure. He is intervening. The Cabinet Minister will reply in due course. You don't worry about that.

SHRI EKANATH K. THAKUR: But, Sir, listed Members have not spoken ...*(Interruptions)*...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Sir, is he speaking as a Member of this House or what?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): He is intervening as MOS, Water Resources. And, this is a part of the procedure... (*Interruptions*)... One second, please ...(*Interruptions*)... This is a part of the procedure...(*Interruptions*)

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: He can reply to it. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Yes, after him, he will get a chance. This is a part of the procedure. Don't worry. This is the procedure. Please go ahead. You please don't take a very long time.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: This practice was there earlier. As I am a new Member, I do not know the procedrue.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): If you are a new Member and you don't know the procedure, I have explained to you the procedure. What more do you want?

यादव साहब, आप जल्द खत्म कर दें।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: उपसभाध्यक्ष जी, मैं पांच मिनट में खत्म कर रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि बाढ़ से जो तबाही हुई, उसके बाद यह टास्क-फोर्स बनाया गया और उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट आ गई है। अब उस रिपोर्ट के आधार पर, जो पूरे उत्तर बिहार में बर्बादी हुई या असम में बर्बादी हुई या पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके में बर्बादी हुई या पूर्वांचल, अरुणाचल प्रदेश में बर्बादी हुई, उसके लिए कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। इसमें गार को हटाना, बांध का उच्चीकरण करना, उसका विद्युतीकरण करना, जो इरोजन हो रहा है उसका बचाव करना, आदि कार्यक्रम हैं। इसी के साथ, यह नेपाल का हाई डैम जब हम बनाएंगे, तो इस बाढ़ की बर्बादी को रोकेंगे, जिससे जान-माल की हानि हो रही है। इसलिए यह 1800 करोड़ रुपया दिया गया है इसमें और गंडक बेसिन को दिया गया है 300 करोड़ रुपया। इसके साथ-साथ अन्य कई स्कीमें हैं, जिनके माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे हम बाढ़ से बचाव करें, कैसे खेतों में पानी पहुंचाएं, कैसे इन खेतों में पानी पहुंचा कर आम लोगों के लिए कृषि के क्षेत्र में उपज बढ़ाने का काम करें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो टास्क-फोर्स बनाया, उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जहां तक जो जल संसाधन विभाग के माध्यम से काम

होने हैं, उनको पूरा करके देश भर में एक अच्छी सिंचाई का प्रबंधन करना, जो भूजल है, उसका बेहतर उपाय हो, मौसमी जल का संग्रहण हो, भूजल का दोहन न हो, और जहां आर्सेनिक फ्लोराइड है, ऐसी जगहों पर वहां के पानी को स्वच्छता प्रदान करना, इसके लिए बेहतर उपाय, प्रबंधन हो और लाभकारी योजना बनाई जा रही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो सिंचाई विभाग है, जल संसाधन विभाग है, इसके कार्यों के बारे में माननीय सदस्यों की जो राय आएंगी, उनको शामिल करके और भी बेहतर प्रबंधन किया जाएगा ताकि हम खेतों तक पानी पहुंचा सकें, बाढ़ के लिए बेहतर प्रबंधन कर सकें और सुखाढ़ से देश को बचा सकें। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।

SHRI JAIRAM RAMESH: Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. I will make five major points in my intervention. First, I will speak on irrigation planning. Second, I will talk on irrigation projects. Third, I will talk about river linking. Fourth, I will speak a little on regional co-operation. And finally, I will speak on the National Water Policy. Sir, on irrigation planning, there are various estimates given by different wings of the Government of India.

If you look at the figures given by the Planning Commission and the Ministry of Water Resources, you get one picture on the extent of irrigation coverage in this country; if you look at the land-use statistics put out by the Ministry of Agriculture and its various counterparts in the States, you get an entirely different picture. But, I will, for purposes of today's discussion, Sir, not get into the controversy over discrepancy in numbers, which is a separate issue in itself. I will also not talk about the difference between the potential created and the potential utilised. This is a well-known problem in India's irrigation planning that there is a substantial gap between the irrigation potential we create and the irrigation potential we actually utilise. I will confine myself, Sir, to the figures that the Planning Commission has just recently put out in this voluminous document on the 10th Five-Year Plan. Sir, if you look at this document, out of 140 million hectares or so of ultimate irrigation potential, it appears as if India has now currently created irrigation potential of about 95 million hectares. In other words, between 65 and 70 per cent of India'a ultimate irrigation potential has been developed. Whether it is utilised, as I said, is a separate issue altogether. Now, Sir, at this rate of addition to irrigation capacity, it looks as if it would take another 20 years or so for India to exploit its ultimate irrigation potential. Now, this

ultimate irrigation potential might itself change. It may go up from 140 million hectares to 150 million hectares with the advances in technology. But, as of today, it does appear as if about 65 to 70 per cent of India's ultimate irrigation potential has been created. Sir, this gives the impression that this is a very significant achievement. But I want to add two words of caution on to this, which, I am sure, the hon. Minister is very well aware of. Sir, when you look at the regional distribution of the irrigation potential that has been created, you will find that there are very large variations, and it is these regional variations that, I would like to suggest, should form the focus of public policy in the balance of the 10th Plan and in the 11th Plan. Sir, if you look at the three big States, namely, Assam, Jharkhand and Orissa, there is a very substantial gap between what the irrigation potential actually is and what the irrigation potential that has actually been created. Then, of course, you have the second tier of States in which you have Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu where there is a significant gap between the two. So, the point I want to make is that while at the all-India level we may be utilising about 65 to 70 per cent of our ultimate irrigation potential, when you look at the level of States, I would argue that there are five or six States, namely, Assam, Jharkhand and Orissa in one category, and Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka in the other category, where there is need for accelerated irrigation development on a collaborative basis between the Centre and the States.

Sir, the second point on irrigation potential is far more important than the regional point which is that even after we develop our entire irrigation potential, 40 per cent of India would still be rainfed. Sir, this is a fact that, I think, we should always remind ourselves of. We talk about India shining; we talk about India as a super power; and we talk about India becoming the fourth largest economy in the world. But the fact of the matter is that India still depends critically, and will continue to depend, on monsoon. If the monsoon is good, India does well; if the monsoon is bad, India does not do all that well. Even by some miracle if in the next 20 years, we utilise all our irrigation potential, 40 per cent of India would still be rainfed agriculture. I think the problems of rainfed agriculture are different from the problems of irrigated agriculture. This, of course, is not something that the Minister for Water Resources is directly concerned with, but, I do believe, that if the Government is looking at water resources in a comprehensive manner, it cannot run away from the problem of this dry land agriculture

which is very substantial, as I mentioned to you about 40 per cent of cultivated area.

Sir, let me now very quickly talk about the second issue which is irrigation projects. Now, Sir, here I want to talk about the Accelerated Irrigation Benefit Programme that was started in 1996-97 when the United Front Government was in power.

This was basically, Sir, meant to accelerate the implementation of irrigation projects. This was supposed to take last-mile problem, take irrigation projects and put them to completion. Sir, almost eight years after AIBP, the record is far from satisfactory, and I am sure that the Minister for Water Resources himself would agree with the numbers that I have. Again, there are some minor variations in the numbers that the Finance Ministry has put out in the Economic Survey, the numbers that are available on the website of the Ministry of Water Resources, but the broad feature is that 181 projects were taken up for completion under the Accelerated Irrigation Benefit Programme, and as of now, only 32 projects are actually being completed. So, Sir, this is not an Accelerated Irrigation Benefit Programme. This is an irrigation benefit programme, with the same pace of progress that we have seen in the past. There is nothing accelerated about it, if these numebrs are anything to go by. Therefore, I would argue, Sir, that we need to pay far closer attention to the way the AIBP has actually been implemented. Sir, I am a Member of the Public Accounts Committee, and the CAG has done a performance appraisal of AIBP, which was a very comprehensive assessment of the manner in which AIBP is actually being implemented. We took two States, Karnataka and Andhra Pradesh, for intensive study, and the picture that emerges, is not very, very positive. I know some changes have been made in the manner in which the scheme is being implemented, but I would urge the Minister to give this a completely different orientation than has been the case so far. Sir, one of the adjuncts of the Accelerated Irrigation Benefit Programme was that the States were supposed to enter into MoUs for reforms in the irrigation sector. One of the conditions in the MoUs is that in five years' time, the States would increase wate charges so that they will be able to recover the O&M costs in five years' time. Now, I would like to ask the Minister how many States actually are following this MoU, how many States are utilising AIBP as a window for introducing reforms. I would like to ask in how many areas has the Central Government used its leverage on the Accelerated Irrigation Benefit Programme to push reforms in the

irrigation sector. Sir, the most disconcerting and the most disturbing aspect of the AIBP is—the Finance Minister is not here, he is the real villain of piece; it's not the Minister for Water Resources—this year the Budget has increased the allocation for the Accelerated Irrigation Benefit Programme from 2,800 crores to 4,800 crores. But actually, Sir, the window is not going to be the additional Central Government assistance; the window is going to be the additional borrowings by the State Governments. Now, what is going to happen is that the poorer States, the fiscally bankrupt States, will not be able to borrow, and even in the States that can borrow, like Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Karnataka, etc., the exchequer will borrow, and it will go for ways and means; it will not come for irrigation projects because we all know that the fiscal position of the States is very poor. I am making a prediction that, in fact, AIBP is going to suffer quite considerably in 2005-06 because the manner in which the Finance Minister has implemented the recommendations of the 12th Finance Commission, and I would urge the Minister for Water Resources, I know he has taken this up, I know he is helpless in this regard, but I do believe that the message should go to the Government that if irrigation is going to be the cornerstone of Bharat Nirman, you cannot take the route of market borrowing by States in order to fulfil your targets under irrigation benefit. I think the poor States will be hurt, and even in the well-off States, the irrigation sector is not going to get the money that it actually deserves. Sir, there is one more number that I want ot give which I am sure, the Minister is well aware of, and this is there in the Tenth Plan document, and this is a very depressing and disturbing number, and it really summarises what is wrong in our irrigation sector. Sir, since 1951, according to the Tenth Plan document, there have been 1,300 irrigation projects that have been taken up for implementation, out of which, only 900 have actually been completed. So, in this country today, there are 400 irrigation projects being implemented at sub critical levels of financing, and I think, really this reinforces the point that I want to make that it is really project implementation, projects under implementation, that need to be completed. You don't need a new category called 'projects under contemplation'. What you need is to take projects under construction, complete them, and then move on and start new projects. The tendency in our system is to start new projects, and not complete the existing projects. We all know why all of us are more keen on starting new projects than completing the existing projects.

Sir, let me now very quickly move to the third point which is river-linking. Sir, so much has been said on river linking. This was made the touchstone of Indian nationalism by the NDA Government. I do not know what more I can say, but I do want to say two things on this entire river-linking scheme.

Sir, there is an Integrated Water Resource Development Plan. This is the Report of the National Commission for Water Resource Development set up by the Ministry of Water Resources. That submitted its Report in September, 1999. Sir, I am just reading from page 9 of its Summary. This is an official, Government of India document. This was submitted to the Ministry of Water Resources. And it is so confidential that when I asked for this Report, without casting aspersions on anybody, I should say, I got a small note from the Ministry, hand written, saying that "Volume-II is highly confidential for which a specific request has to be made, and get the written approval of the Secretary or the Minister." But I did manage to get Volume-I, which is obviously in the public domain. What does Volume-I say? Volume-I says:

> "The Himalayan river linking data is not freely available, but on the basis of public information, it appears that the Himalayan river linking component is not feasible for the period of review up to 2050."

And then it goes on highlighting what the problems are in the entire plan of linking the Himalayan rivers.

The VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Is it a confidential report that you are disclosing to the public?

SHRI JAIRAM RAMESH: No, Sir. It is a public document, published by the Ministry of Water Resources.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): No; no; you yourself have said that; you quoted something.

SHRI JAIRAM RAMESH: Volume-II is a map, and it says Volume-II is confidential. But Volume-I is not confidential.

The VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): You are quoting from Volume-I.

SHRI JAIRAM RAMESH: I am quoting from Volume-I. I am not breaching the official secrets. But I don't have Volume-II.

The VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): You will be in trouble; that is why I thought I should warn you.

SHRI JAIRAM RAMESH: As far as the Peninsular river component is concerned, the conclusion of this National Commission for Integrated Water Resources Development is that "there is no imperative necessity for massive water transfer. The assessed needs of the basins could be met from full development and efficient utilisation of intra-basic resources except in the case of Cauvery and Vaigai basins. Some water transfer from Godavari towards the south should take care of the deficit in the Cauvery and Vaigai basins."

Sir, the point which I want to make here is that the entire weight of technical opinion has been to proceed with caution on the river-linking scheme. Even the National Water Resources Development Agency has identified 30 links, out of which a pre-feasibility study has been done for all 30, and feasibility studies have been done for eight. If you look at the actual feasibility study, one feasibility study that is actually put on the website of the Ministry, which is Ken-Betwa link for which a feasibility study has been done, even there, you will find, not only from a financial point of view, not only from a project implementation point of view, but also from a human and ecological point of view, that the implications of this river-linking scheme are going to be quite stupendous and quite enormous. Rather than making the river-linking scheme the touchstone of patriotism, rather than making the entire scheme to be the litmus test of who is Indian and who is not Indian, by these self-styled patriots, I think we should go cautiously. It is not as if we have not done river linking. Rajasthan canal is a river-linking scheme. the Telegu-Ganga is an intra-basin transfer. It is not as if India has not done an intra-basin transfer, but on the scale and magnitude that is being talking about, I think we need to proceed with some caution; obviously, it needs to be sequenced. There may be some cases where intra-basin transfers could be financially feasible, but I do believe that intoday's day and age, with today's media, with today's civil society, it is not possible for us to overlook the ecological and human population resettlement consequences of such a massive scheme. Yesterday, you would have seen in the newspapers, Sir, that there is a new study that has come out, that has called into question the utility of Bhakhra Nangal Dam. Sir, even todays' day and age, I do not think that we can rush into this project oblivious of the consequences of resettlement of

millions of people, and let us also face it, Sir, India's track record in resettlement and rehabilitation has been pathetic, has been poor. This is a blot on our collective conscience.

With the type of track record that we have had, if we embark on this fanciful scheme of river linking with 30 storage reservoirs involving massive displacement of people, I think, it is going to be fraught with grave consequences. Therefore, I would urge upon the Minister to follow the route that is recommended in the Common Minimum Programme, that is, to take up those schemes which have overriding priority to us and, obviously, some of those States which are involved plus other States.

Sir, I will just take three or four minutes. The fourth point I want to talk about is regional cooperation. It is a fact that many of the problems that we face in water resources planning cannot be looked at in isolation of our neighbours. The problems of flooding, for example, in north Bihar, cannot be solved on a long-term basis without cooperation with Nepal. Similarly, when we are talking about the development of the entire eastern Himalayan region, not only covering eastern UP and Bihar but also the North-East, this cannot be done in isolation of Bhutan and Bangladesh *vis-a-vis* water sharing. The history of regional cooperation has not been very positive. We have the Mahakali Treaty with Nepal which was signed in February, 1996. We have the Ganges Treaty with Bangladesh which was signed in December, 1996. But barring these two Treaties and barring the joint ventures that we have in Bhutan, of which the Chukha project is the most outstanding example, our track record of regional cooperation has not been vey positive. India has preferred to deal with this issue bilaterally. We have dealt with Nepal bilaterally. We have dealt with Bhutan bilaterally. We have dealt with Bangladesh bilaterally. Perhaps, that is the only way to deal with this, given the politics of the sub-continent. But I would urge upon the Minister not to close the regional cooperation route. The Common Minister Programme talks about regional cooperation for the eastern Himalayan, rivers, Ganga-Brahmaputra-Meghna basin. I think, maybe, it is a fanciful idea today, but 10 years from now it is possible for us to envision a major initiative on the eastern Himalayan rivers which would encompass not only India but also Nepal, Bhutan and Bangladesh, and I would even venture to suggest to bring China also into this entire venture. By all means, let us go through the bilateral route, though the bilateral route itself has many problems. Even on the Mahakali project, I don't

know-the DPR on the Pancheshawar project was supposed to have been completed some years ago-wheather the DPR has actually been completed. So, we have not been abie to make much progress even with the bilateral treaties. But, by all means, let us keep the bilateral route open. In addition to the bilateral route, let us also open the regional cooperation window. India should take the initiative to set up a Himalayan Rivers Commission or a Himalayan Rivers Consortium to develop this on a partnership basis.

Sir, finally, I come to the National Water Policy. The Government of India came out with National Water Policy in 1987. Then there was a Revised National Water Policy in 2002. It is a very slim document. If you read the National Water Policy, you will find that it talks about everything under the sun. All the good things of life are there in the National Water Policy. There is nothing missing, including communal harmony which, I am sure, the National Water Policy will aim at. But the real questions are: How is the National Water Policy going to be implemented? What are the legal principles? What is the legislation required? What is the executive action required? What is the mechanism of consultation between the Centre and the State? For example, the National Water Policy says that the Inter-States Water Disputes Tribunal Act. 1956 will be reviewed. For what will it be reviewed? With what end in mind will it be reviewed? To create what net result will it be reviewed? I think we need to go from a statement of principles and good objectives, which the National Water Policy certainly is, to a much more operational document to operationalise and implement many of the worthwhile ideas that have been floating around in all these documents, which have finally been embedded in this National Water Policy.

Sir, let me conclude by saying that this is a very important segment of planning. Water resources along with land resources are going to develope our economic potential. The Government of India has set up a National Water Resources Council. It is a sad commentary actually-I am open to correction by the Minister-that the National Water Resources Council last met on 1st April, 2002.

If it is going to meet once in three years or once in four years, there is no point for us to say that water resources are very important, if that importance is not reflective in the actions that the Government takes. Whether it is the NDA Government or the UPA Government, is not the issue. The issue really is what importance the Central Government attaches to this subject. Sir, unfortunately, the limitation is, every time you push the Central Government, the Central Government will say this is

a State subject. We are reminded of Shri Fali Nariman's intervention this morning on the the Naxalite issue. The Minister said that this was a State issue. Similarly, in water resources, up to a point you say, "We will do it". But when we push the Central Government says, " It is a State issue". I think we need to get out of this conundrum because water is a national issue. It is not a Central issue or a State issue. I think it is a national issue. I think it is time for us to recognise water as a national issue. Give it that status and treat all the consequences flowing from that, from a planning and from an implementation point of view. Thank you.

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): M. Vice-Chairman, Sir, I, wish to draw the attention of the House to the issue of water shortage the country is likely to face in the next 10 to 15 years. Water is likely to become an explosive issue in the days to come and it is for the Government and the Minister of Water Resources to rise above narrow, petty and parochial considerations to deal with the situation. As far as water availability is concerned, the country can be divided broadly into two parts. The part from Jammu and Kashmir down the Gangetic plane to West Bengal has the benefit of Himalayan rivers and so long as the Himalayan glaciers continue to be perennial, they are not likely to face any major problem in the next 50 years. There is the peninsular India which has few perennial rivers, that is likely to face the brunt of the water problem. The peninsular rivers are mostly rain-fed and once the monsoon fails, the rivers become bone dry.

In fact, these two zones will have conflict of interests in the days to come. The States in the Gangetic plane, which wield considerable political clout in the Indian Parliament, are not going to spare their surplus water to deficit parts of their own motherland.

This is reflected in the decision of the Task Force set up by the NDA Government on the linking of rivers between varius regions of the country. The Task Force, if I may recall, was not constituted because of political conviction of the BJP political establishment but because of compulsion caused by the Supreme Court directive. Instead of addressing the problems of peninsular India, which is reeling under severe water shortage for the past several decades, the Task Force recommends the linkage of Ken Betwa rivers in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan. The Gwalior

region, which is beneficiarly of the scheme, belongs to the former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee.

So, even before the ink dried on the Task Force recommendation, Shri Vajpayee formally inaugurated the project, days before he stepped down from office. The present Water Resources Minister, who is from West Bengal, also seems not keen on diverting water from the Himalayan Rivers to Peninsular India. Such a move, he feels, will hurt the interests of West Bengal. So, he has also plumped for Vajpayee's project notwithstanding his aversion for his political ideology.

Sir, as a result of this, the Southern States will have to wait for 50 years for Ken Betwa to be linked before the Central Government thinks of linking the Peninsular India. I can understand the BJP, which as no political presence in Southern India, ditching these States. But the Congress has presence only in Southern India. The Congress is a ruling party in Maharashtra, Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Kerala and Pondicherry. The Party has minimal presence in Northern India. The Congress, on its own, secured only three MLAs in the recently concluded Assembly Elections in Bihar. The seven other Congress MLAs got elected due to the courtesy of Shri Lalu Prasad Yadav. But the Congress-led UPA Government which has DMK, PMK, MDMK, as constitutents, has betrayed the people of Southern India. To protest against the betrayal, I would urge upon the 40 Lok Sabha MPs from Tamil Nadu, without whom this Government cannot function, to either tender their resignation or face the wrath of the people in the coming Assembly elections next year. I demand that the river linking projects in the Southern Peninsular India should be taken up simultaneously with the Ken Betwa project to send a message that the UPA Government does not treat the Southern States as its colony.

The hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram, announced with fanfare in the last Union Budget to set apart Rs. 1,000 crores for setting up the desalination plant in the Chennai city. The Chennai city, with one crore population, has no piped water supply for the past two years. The per capita availability of water in Chennai city is the lowest in the country. Sir, instead of making announcements which remain on paper, the Central Government should fund the setting up of desalination plant for which the Tamil Nadu Government has finalised international competitive

tender. The Central Government should fund the project on a grant basis since the Chennai city alone contributes about Rs. 20,000 crores to the country's foreign exchange kitty by way of exports. So, the Central Government should not mind giving one time grant of Rs. 1,500 crores for putting up desalination plant at Chennai.

I also demand that the Centre should enact a legislation to nationalise all rivers so that petty and parochial consideration do not come in the way of implementing the worthwhile inter-State river water projects.

Sir, my State is having serious differences with Karnataka on sharing the Cauvery Water. My State has not been getting justice during the regime of both the national parties. It is unfortunate that the DMK, which was part of NDA Government and is now a part of the UPA Government, has betrayed the people of Tamil Nadu on the Cauvery issue merely because they did not get power in Tamil Nadu. Karnataka's political constitutency is cultivated by both the Congress (I) and the BJP.

That is why the Centre has failed to take steps to complete the work of the Cauvery Water Disputed Tribunal. The Tribunal was set up twenty years after the dispute had surfaced. It is almost fifteen years since the Tribunal has been functioning, but it is yet to give its final award. It shows how partial the Central Government is against Tamil Nadu where, neither the BJP nor the Congress, is a political force. The BJP and the Congress may fight mock battles in Parliament, but on Cauvery water dispute, they collaborate and ensure that Tami Nadu is given a raw deal. For the past three successive years, there has been no cultivation of paddy in Tamil Nadu due to non-receipt of Cauvery water from Karnataka. I warn the Central Government against this raw deal meted out to Tamil Nadu. Such an unhelpful attitude of the Centre will only give a fillip to the secessionist forces operating in my State. My Chief Minister, Dr. Puratchi Talaivi, is taking these forces head on. But the Centre, by being deliberately partial, is fomenting their growth.

On the direction of the Supreme Court, the CRA was formed. The Prime Minister is the Chairman and the Chief Ministers of the four concerned States are members of the CRA. The job of the CRA is to implement the interim orders of the Cauvery Water Disputes Tribunal. But the CRA has failed to implement the interim orders of the Tribunal because it has no power, at all, in this respect. The CRA was not able to finalise even the

distress-sharing-formula'. So, power should be given to the Chairman of the CRA to, at least, compel the erring States to implement the interim orders of the Tribunal and penalise the erring States. But the CRA is lacking in this power. So, I demand that the Government should take strong steps to implement the orders of the Tribunal and the Supreme Court.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Shri C. Ramachandraiah. You have seven mintues, please.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Sir, I heard with rapt attention the speeches of hon. Members on this issue. I am rather constrained to accept most of the observations made by Shri Jairam Ramesh. He dealt with capital formation and with how these projects have not been completed within the stipulated period.

Sir, water is a very important input in agriculture. Unless we increase the growth rate in agriculture, we cannot achieve the proclaimed growth rate of eight per cent in this country, which is badly the need of the hour. So, achieve a growth rate of five per cent in agriculture, we require a growth rate of five per cent in irrigation. For that, we require more than eight to nine thousand crores of rupees, which amount is given in this document here. We have twenty river basins, out of which six are under total stress conditions and which are depleted. Five more will become water-scarce by 2050. Only three are going to remain there with adequate water potential. This is the picture that has been given in this document.

Sir, the need to the hour is to improve capital formation. If you go through the amounts that have been pumped into the irrigation sector, you will find that in the First Five Year Plan, it was 18.4 per cent of the total capital formation in the country. In the Second Plan, it was 13.2 per cent; in the Third, 13.4 per cent; in the Fourth, 14.3 per cent; in the Fifth Plan, it was 15.7 per cent. And the decline started from the Sixth Plan.

It was 11.6 per cent in the Sixth Plan; 8.4 per cent in the Seventh Plan; 7.3 per cent in the Eighth Plan and 8 per cent in the Ninth Plan. Today, the capital formation in agriculture is around 8 per cent of the total capital formation of the country. The sector which is contributing more than 25 per cent of the GDP and more than 60 per cent of the population make their living on this profession, the entire House can see the disparity in the

capital formation. From 1960-61 to 1999-2000, within a span of 40 years, it has been increased by four times from 52.58 billion rupees to 213.88 billion rupees. Sir, the share of agriculture in the overall gross capital formation in 1951-52 was 21 per cent, and now it is 8 per cent. So, this is a very poor picture that is being presented. Unless we lay more emphasis on capital formation in this sector, we are not going to achieve much. Unless we invest more funds in agriculture, i.e., in irrigation, we cannot find any panacea for the ills of this country.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SARLA MAHESHWARI) in the Chair]

Madam, as far as water utilisation is concerned, I would like to inform the House that around 85 per cent of water is being utilised for agriculture and the rest 15 per cent is being utilised for domestic needs, industry, ecology and other things. So, the need of the hour is not only water harvesting but also consevation of water. So, we have to go in for sprinklers and drip irrigation where we can reduce water consumption and optimum productivity can be achieved. But, the budget allocation which has been made is a very small pittance. It is nowhere useful to the objective that has to be achieved. The Task Force, headed by Shri Chandrababu Naidu had recommended Rs. 10,500 crores for the sprinkler irrigation

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Micro-irrigation.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Yes, for micro-irrigation. But, a sum of Rs. 500 crores has been allocated for its, which is a very small amount. So, the entire agricultural sector has to be re-oriented. Unless you re-orient the entire sector, we are not going to achieve the result. Continuously, we will be talking about agriculture, chanting the cause of agriculture, and ultimately there will be no result. This is the time we should go in for drought-resistance crops and salinity-resistance crops.

Madam, there is one more issue. The productivity of agricultural products is very, very low when compared to other products. Whatever MSP you give, unless the productivity goes up, it will not be helping the farmer. So, that is also very essential.

Madam, now I come to the funding of the projects. It is a State subject, as most of the Members have said. Thanks to the Twelfth Finance Commission which has transferred the responsibility of borrowings to the States itself. They are rather wise-enough to press the pass button. Now, they ask the States to borrow the funds. With all leverage, with all resilience,

when the Government of India cannot borrow, when the Government of India cannot maintain the fiscal deficit, how can you expect the States to achieve this? So, it will be very, very difficult for the States to raise the funds. I have got my own justified apprehensions that the irrigation sector will be the greatest casualty in the States in the future. No mechanism has been prescribed; no mechanism has been informed to the States. The States which are unable to raise the loans for funding their Plans, how can they raise those funds, if the Government of India do not come to their rescue? So, it is all confusion that has been created for raising of these funds. In the future, we need Rs. 90,000 crores to achieve this irrigation potential.

Till now, I was told that Rs. 88,000 have been spent, and we are able to irrigate 91 million hectare. By 2020, we have to double this. For that, we require an investment of Rs. 90,000 crores. Now, the Government of India has got its own old slogan 'it is a State subject', so you go to the market and borrow. Seventy per cent of the funds collected by you are being retained by you, and a paltry 30 per cent funds are being given to the States as devolution of funds. And you expect the States to implement all these projects!

Unless you orient your entire funding basis, it is very difficult to achieve these targets.

The second important issue is the constraints we are facing in inter-state water disputes. Though it was enacted in 1956, we could not solve the problems; because of various reasons, political and other regional problems, the Government of India-I should say-is not that active in solving problems of the States. Of course, in 2002, the Government of India has been conferred with the power to stipulate a time-frame within which a problem has to be solved; but even then, it is not done. I can bring umpteen number of cases, to the notice of the Government of India, where neither the Government of India nor the lower riparian States, have been informing about construction of projects in upper riparian States. The awards that have been given by Tribunals are not being honoured. I don't want to create any controversy. But, ultimately, the victim is the lower riparian State, It is the case with all lower riparian States, and this has to be arrested. How best it has to be done, should be considered.

The issue of linkage of rivers has been there and it has a mixed reaction. But whatever it is, whether you link rivers or you do something else, you

have to provide irrigation to every acre of the land in this country. Then only the income of the major section of the population would go up. So, that is the need of the hour. I am not an engineering expert nor an ecological expert where I can weigh the pros and cons. But I read some success stories of linkage of rivers in some other countries. Let us study the positive features, the negative features, weight them and then proceed. When thousands of farmers are committing suicide, let us maintain the equilibrium, let us maintain the balance where ecology is maintained; at the same time, let us go ahead with projects and provide irrigation to the poor farmers of this country.

Lastly, Madam, I have been telling umpteen number of times that agriculture is the panacea for all ills of our economy. Agriculture alone is the panacea. As long as you adopt a lop-sided policy towards agriculture, we are not going to achieve growth. All along, we have been suggesting things. All Government have been adopting mis-placed priorities. So, agriculture has to be given the priority. See, for example, China. We have been quoting China for its success stories and other things. We should not forget that it is because of the agricultural growth, continuously for one-and-a-half decade, they could be able to achieve that growth. So, let us give more money to the major section of the population to buy. Then only you can create the demand for goods. So, that is the only solution. Though we have the Ministry of Water Resources, but, ultimately, the projects have to be implemented by the States only. There is this anomaly. Water is a State-subject, but water disputes is a Central-subject. And no State is complying to the awards. How to solve all these problems then?

On the Cauvery dispute, the interim award has been given. Till now, subject to correction, no final award is given. I don't know how many decades would it take. So, it is causing constraints also as far as the national integration is concerned. My humble request to the Minister is to pay attention to the important problems. You should have a vision. The vision should have a plan for implementation. Unless you implement a plan, it will be redundant. For implementation of a plan, you should have the political will also. I am very confident that this new dispensation, the UPA, has got the political will to solve the problems. Specially, the lower riparian States' interests have to be protected. Then only the problems will be solved and it will be in the interest of the integration of the country. Thank you.

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (Rajasthan): Madam Vice-Chairman, I have the honour to make certain submissions but no pretensions to tell the hon. Minister of Water Resources how to run his Ministry. I come from Rajasthan and Rajasthan has certain legitimacy and credibility of claiming certain very special privileges at the door of the Water Resources Ministry. I will seek the permission to put them across rising above party factions and lines. I will reiterate a very important viewpoint, which has been put forward by Dr. Jairam Ramesh that water has to be taken as a national resource. Everybody agrees that water is a scarce resource, water is a vital resource, water is a rare resource, water cannot be produced in laboratories and water is God's gift. But until and unless we believe and really act that way that water is a national resource, inter-State disputes would not be resolved. One of the main functions of the Ministry is considered to be mediation and resolution of conflicts between States regarding water resources. Rivers do not know geographical bundaries. The Ganges will start from Gangotri and will go up to Gangasagar passing through so many States and regions. It may be the Cauvery or it may be the Krishna or it may be the Godavari or it may be the Chambal or it may be the Ravi or the Beas or the Sutlej or the Yamuna or the Narmada. They all are sacred rivers of the country and not of any particular State. If that is accepted, Madam, there would not be abrogation of a treaty from one side. You see, no State Chief Minister will rise one day and say. 'Today we negate and abrogate the treaty which was entered into by the then Prime Minister of the country and by the then Chief Ministers of Punjab, Haryana and Rajasthan combined together on 31st December, 1981 and a decision was taken that this will be the share of different basis of different States." Suddenly one day it comes into the mind of a power drunken person to call that "I will do unilateral abrogation of this treaty which is of national importance and which is a federal treaty." We begged at the door of the Ministry as well as the hon. Prime Minister. The Chief Minister of Rajasthan along with all the MPs, cutting across party lines from Rajasthan, put forward the case and requested and begged, 'kindly intervene, put a proper sense in the State and resolve the issue.' Ultimately, the matter has gone to the Supreme Court through a Presidential reference and Rajasthan has not been able to get its due share. It is not a question of Rajasthan. The same is with Tamil Nadu, the same is with Karnataka or with other warring States. It may be Madhya Pradesh or Rajasthan. It may be Yamuna-Sutlej link or whatever is there. So, this one point, which I would submit, is

that some kind of a mechanism should be evolved to solve the inter-State disputes. As far as Rajasthan State is concerned, area-wise it is the largest State in the country. It is the biggest desert State in the country.

It is the most drought prone State in the county. It is the highest famine stricken State in the country. Out of the four consecutive years, three years are of famine. That is the pattern there. It is a State which unfortunately has the lowest water resource potential. It is the *Daridranarayan* among States and it asks *Varun Devta* of water resources to give it some special share, to give it some special status. It has State geographical area of the whole country amounting to 10.4 per cent. It has population of 5.2 per cent. Cattle population is 18.7 per cent which is the largest in the country. Cattle need more water than human beings. Overall share of the State in surface water of the counry is 1.16 and overall share of the State in ground water in the country is 1.72. Out of this total share, surface water is only 9 per cent. Out of the total geographical area, 58 per cent is desert consisting of 12 districts. Such a plight you will not find in any State and hence, we keep on begging, 'give us something more'. Let it not be proportionate to our population or our area. But let people not go thirsty. In Rajasthan, water is precious than ghee or water is more precious than nector, if I say so, I hope it won't be an exaggeration. It is a ritual with the ladies in the villages that they trek few miles with a pitcher on their heads to fetch water from somewhere. Hon. Minister will be surprised to hear that out of flourosis affected villages of the country there are total 32,311 villages in our country and share of Rajasthan is 16,500. Fifty per cent of the total flourosis hit villages of the country are in Rajasthan. You can see hunch-backs of water dams in so many villages, prematurely decayed, aged, with bent backs. It is a pitiable sight. Salinity is throughout the whole State. It is rarely that you find underground water sweet. Very few districts are there where water is sweet otherwise it is brackish or saline. At many places, in addition to that there is nitrate also. It is a miserable plight of the people. When we talk of drinking water, I will again repeat what Dr. Jairam had said. He pointed out two things. Whenever we put forward any request to the Ministry of Water Resources, two alibis are ready. One is, it is a State subject. It may be some kind of a river, it may be flood management, it may be drinking water. One is alibi that is a State Subject, so don't bother. Another alibi is very interesting, multiplicity of ministries. Water is a resource. If a commoner asks for drinking water he

does not understand what is the difference between Water Resources Ministry or other Ministries who handle water. If I request Shri Priyaranjan Dasmunsi for a bucket full of water for drinking, He will say 'it is not my Ministry which handles it'.

Out of courtesy, he might give me a bottle of Bislery, which he gave when I went to his Ministry as a Member of the Consultative Committee. But, can we provide Bislery to 6 lakh villages of the country? My submission is that the subject of water resource development and management, which is so vital and important, should be handled by only one Ministry under one umbrella, not by several Ministries at the Central Government level, namely, Water Resources, Agriculture, Rural Development, Urban Development, Power, Shipping, Environment and Forests and so many. Tomorrow, it may happen that there will be another Ministry for the water used for washing clothes and another Ministry for water used for taking bath. And, funny thing is that Secretary is common to both of them. Secretary (Water Resources) and Secretary (Drinking Water) is the same. Why not have the same Minister? I think our hon. Minister is capable enough to handle it. This is suggestion not from me, but it is a suggestion by the National Development Council made in its 50th Meeting held on 21st December, 2002. This is a suggestion by the Planning Commission also. However, it is for the Central Government to take a decision. This is one submission for the overall situation which I wanted to make.

As far as Rajasthan State's woes are concerned, I would just like to mention one or two points only for the consideration of the hon. Minister. One is about the inter-linking of rivers. It is neither a baby of the NDA, nor a baby of the UPA. It is a matter of national concern. As a Member of the Standing Committee as well as Members of the Consultative Committee, we all felt irrespective of all party lines, that inter-linking of rivers is the only way to solve in the long run and the flood as well as famine situation. Flood and famine are, what should I say, twin sisters and they can be handled only through inter-linking. It may take a decade or two; nation's life is very long. But, about this, we must have a determination and a kind of pledge that it must come up in due course of time. As far as Rajasthan is concerned, I am grateful to the hon. Minister. He had assured that one proposed small link pertaining to Parbati, Kali Sind and Chambal rivers will come up soon because through his kind persuasion, Madhya Pradesh and Rajasthan will come to an agreement and understanding. Another two

small links are also there pertaining to Yamuna Rajasthan and Rajasthan Sabarmati, which belong to Himalayan content. I know hon. Minister is aware of it and something will soon come out of it. As far as Beas and Sutlej is concerned, I will again request that 60 MAF, which is due share of Rajasthan, must come to this thirsty State. Rajasthan State has nearly exhausted its patience because this agreement took place in 1981 and now it is 2005. Much water has flown under the bridge since then, but still, the agreement has not been honoured. Another submission was regarding MoU between Haryana and Rajasthan for utilisation of Yamuna waters. This has also been lingering for years and years. Governments have changed, but justice has not been meted out.

Another submission is regarding Indira Gandhi Canal Project that is known as *Maruganga*. It was earlier known as Rajasthan Canal, but later on, it was named as Indira Gandhi Canal, in memory of that great lady, hoping that the scheme will come through very soon. 46 years have passed since the Indira Gandhi Canal Project started. It was started in 1958. (*Time-Bell*). Madam, 46 years is very long period, and, it will keep going on further and further if the Centre does not grant lum sump amount in one go.

If you keep on giving money in instalments, escalation takes place and this never ends. My request to your honour is to consider it because it is a national project. Already, 14.10 lakh hectares has been commanded, under Canal water, and, total area which has to be covered is 19.63 lakh hectares. We can add five lakhs more provided lump sump grant is given. I think demands are endless but I will just make one point regarding flood scenario in the country because the Minister of State had referred to it. Your honour, I think, I will take two-three minutes more. Again, here in the Statement recorded or supplied by the Ministry, it is a State subject. But is it a national calamity, and, if you look into the figures, you will find that it is a calamity, which is ten times more than the Tsunami calamity. The figures are very revealing and horrifying, and, the scenario is so grim.

According to the figures supplied by the Ministry—I am quoting statistics— during last fifty years, nearly 79,500 to 80,000 human lives have been lost in floods, forty seven lakh heads of cattle have been lost - it is a staggering figure if you think of it - and, damage worth 90,250 crores of rupees has taken place. In the year 1979, in one year alone, 6,18,248 cattle heads, and, 11,316 human lives were lost. It is a havoc, it is a scar,

and, things won't improve if the implementation is not correct. So far, nearly one lakh crore of rupees have been spent in flood control but the money has flown along with the water to the sea. It might have been pocketed or whatever happened, I don't know, but floods have not been controlled so far. This is grim situation and it needs very special care.

Rajasthan is not one of the States that is affected but these are the States of the country and I think because the Minister of State referred to it, I pointed it out.

Another point is 'small is beautiful'. I am again quoting statistics, Irrigation capacity, created in the Minor Irrigation sector, covers about two-thirds of the country's total irrigation capacity. It is cost effective. So let us pay more attention to that, and, under this scheme comes repair, renovation and restoration of water bodies, for which very little has been done. Only 100 crore of rupees have been earmarked, and, out of around 600 districts in the country, only 17 water bodies in 16 districts of the country have been selected. I don't know what the criteria is of selecting these 16 districts. Rajasthan is not one of the States that have been considered. I am not aware which are the lucky States that have those 16 districts, but see what a paucity it is.

There are a few lakhs of water bodies, old tanks, old *bawris;* by desilting, they can be utilised, Creation of new water body is very difficult. So this is the point which needs attention. I will just say what Mr. Chidambaram had said in his last year's Budget Speech, "Restoring traditional water storage bodies is very essential. They have fallen into disuse. Many of them have accumulated silt. Many require urgent repair." He said, "The crisis of water, the biggest crisis of the 21st century, has affected the lives of millions of our fellow citizens". But they were all false sops, promises and hopes. Nothing came out of it. I know, and I am sure, through your timely mediation, Madam, our hon. Minister will pay his attention to these matters which are already in his view and something very tangible will come out of it which will make him not only *Varun Devata* but will make him a *Bhagiratha* of this country also if water problems-drinking as well as irrigation - is solved for the poor farmers. Thank you, very much, Madam, for your kind indulgence with which you have heard me.

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार) : महोदया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। आज पानी की समस्या किसी गांव की समस्या नहीं रह गई है या किसी प्रदेश की समस्या नहीं रह गई है।

आज यह एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में देश के सामने खड़ी है। आज पानी के लिए, एक गांव दूसरे से लड़ता है, एक प्रदेश, दूसरे प्रदेश से लड़ता है। हमने पानी को राज्य का विषय माना है, हम पानी को राज्य की समस्या समझते हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पानी की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और आने वाले वर्षों में यह समस्या सरकार के सामने एक कठिन समस्या के रूप में खड़ी होने जा रही है। महोदया, आजादी के 57-58 वर्षों के बाद भी अभी तक हम अपने देश के नागरिकों को शुद्ध पानी भी मुहैया नहीं करा पाए है। पानी की कमी नहीं है दुनिया में, दो तिहाई पानी है, मगर वह समुद्र में है। उसका 97 प्रतिशत समुद्र में है, दो प्रतिशत बर्फ के रूप में और एक प्रतिशत से कम पानी हमारे उपयोग में आ रहा है। आज स्थिति यह है कि धीरे-धीरे पानी की कमी होती जा रही है। मैंने एक जगह पढ़ा कि आज से 50 वर्ष पहले जो दिल्ली में भूजल स्तर था, वह 35 मीटर नीचे चला गया है। यह सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है देश के दूसरे भागों में भी धीरे-धीरे भूजल स्तर नीचे चला जा रहा है। जहां पानी एक ओर जीवन है, वहीं दूसरी ओर पानी से तरह-तरह की समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। पानी से बाढ़ की समस्या पैदा हो रही है, पानी से जल जमाव की समस्या पैदा हो रही है, पानी से कटाव की समस्या पैदा हो रही है। कई राज्यों में, जैसे बिहार में, जहां एक ही समय में बाढ़ की समस्या होती है वहीं दूसरी ओर सुखाड़ की भी समस्या होती है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, आपने देखा होगा कि बिहार से जो हमारे माननीय सांसद आते हैं, हम लोग लगातार बिहार की बाढ़ की समस्या के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तरी बिहार के 15 से 20 जिले ऐसे हैं, जहां हर वर्ष बाढ़ आती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं तीन-तीन बार बाढ़ आती है, कभी-कभी तो दीवाली में बाढ़ आई है। ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि बिहार में दीवाली पर भी बाढ़ आई है। जिन नदियों में बाढ़ आती है, वे हिन्दुस्तान में बहती हैं, भारत में बहती हैं, बिहार में बहती हैं, मगर वे नदियां नेपाल की हैं। कोसी, कमला, गंडक, अधबारा समूह, ये सारी नदियां नेपाल से आती हैं। जब नेपाल से इन नदियों में बाढ़ आती है, तो ये भारी विनाश उत्तरी बिहार का करती हैं। हर वर्ष 1500 करोड़ के आसपास बिहार सरकार का पैसा रि-हेबिलिटेशन पर, रिलीफ पर खर्च होता है। मैं कहना चाहता हूं कि हम पानी को राज्य का विषय मानते हैं, राज्य की समस्या मानते हैं, आज की स्थिति में जब देश के कई राज्यों में पानी की समस्या की वजह से कई तरह की कठिनाइयां होती हैं, तो हमें पानी को राज्य का विषय नहीं मानना चाहिए। हमें उसे एक नेशनल इश्यू के तौर पर, राष्ट्रीय समस्या के तौर पर लेना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, श्री जय प्रकाश जी को सुन रहा था और मुझे जानकारी भी थी कि यूपीए गवर्नमेंट ने बिहार को बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए नेपाल सरकार से वार्ता की है। अभी उन्होंने कहा कि सप्र कोशी पर बांध बनाने के लिए डीपीआर के लिए कार्यालय स्थापित किये गये हैं, कमला और बागमती पर भी डीपीआर के लिए सहमति बन गई है। मैं माननीय मंत्री जी को, और राज्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 28 करोड़ रुपया मोकामा में जल निकासी के लिए दिया है। उन्होंने गंडक नदी के लिए भी 300 करोड़ रुपया दिया है।

महोदया, मैं जहां से आता हूं, मेरे गांव से होकर एक बड़ी कमला नदी जाती है। हर वर्ष कटाव होता है, बांध टूटता है, लाखों लोगों को बेघर होना पड़ता है। ऐसा न सिर्फ कमला नदी की वजह से होता है बल्कि कोशी में भी यही समस्या है। उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या है और बिहार ही नहीं दूसरे राज्यों में, असम में, बंगाल में और कई राज्यों में बाढ़ की समस्या है, इस समस्या को जो नदियां उत्पन्न करती हैं, वे सब नेपाल से आती हैं। इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और सरकार विचार कर भी रही है। मैं जानता हूं कि यह दो देशों के बीच का मामला है। हर वर्ष बांध को ऊंचा करना है, क्योंकि स्थिति यह है कि नदी में हर वर्ष सिलटेशन होता है, जिसको गाद कहते है, हर वर्ष नदी में सिलटेशन होता है, सब बांध टूटता है, खेत-खलिहानों में बालू भर जाता है। सिलटेशन की वजह से कंट्रीसाइड नीचे हो जाता है और रिवरसाइड ऊंचा हो जाता है। उस गाद को जब तक नदी में से निकाला नहीं जायेगा, तब तक थोड़ा-सा भी नदी में पानी आयेगा, तो वह बाढ़ ले आयेगा।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि सिलटेशन की जो स्थिति है, जो समस्या है, उस समस्या को सरकार गंभीरतापूर्वक ले। दोनों तरफ से नदियों पर बांध बंधा हुआ है, उसे भी ऊंचा करने की बात है, सुदृढ़ करने की बात है, उसके लिए भी राज्य सरकार के पास आवश्यक कोष नहीं है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि पानी की समस्या, बाढ़ की समस्या कोई राज्य की समस्या नहीं है, उस समस्या को नैशनल ईश्यू के रूप में लेना चाहिए। महोदया, मैंने नेपाल में हाई डैम के बारे में चर्चा की। मंत्री जी को धन्यवाद भी दिया है। कि इन्होंने नेपाल सरकार से बात की है, कई करोड़ रुपए डीपीआर के लिए भी दिए हैं। महोदया, ब्रह्मपुत्र नदी में भी भयंकर बाढ़ आती है। हम सभी जानते हैं । वहां ब्रह्मपुत्र बोर्ड बनाया गया है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गंगा बेसिन को भी बोर्ड का दर्जा दिया जाए क्योंकि गंगा में भी हर वर्ष बाढ़ आती है, भयंकर कटाव होता है, सैकड़ों गांव जलमग्न होते हैं, इसलिए उसको भी बोर्ड का दर्जा दिया जाए। महोदया, पानी को रोकने की समस्या है। वर्षा का जो जल होता है, उसका बड़ा भाग समुद्र में किसी न किसी रूप में चला जाता है और हम उसको रोक नहीं पाते। यह जो जल संचयन की समस्या है, जल को रोकने की समस्या है, उस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि जब तक हम जल को नहीं रोकेंगे, जो भूजल स्तर हमारा नीचे गिरता चला जा रहा है, उसे भी हम नहीं रोक पाएंगे। महोदया, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उस क्षेत्र में दो सौ, चार सौ, पांच सौ मीटर की दूरी पर आपको एक तालाब मिल जाएगा। अभी भी वहां तालाब हैं, बड़े तालाब भी हैं, छोटे तालाब भी है। उन तालाबों में जो वर्षा का जल होता था, उसको संचय किया जाता था, अभी भी संचय किया जाता है। उसमें स्नान करने की समस्या, पशुओं को पानी पिलाने की, धोने की समस्या और सिंचाई की समस्या का समाधान होता था। धीरे-धीरे क्या हो रहा है,

वे तालाब खत्म होते चले जा रहे हैं। उन तालाबों को भी, -- नये तालाब बनाने के साथ—उन तालाबों को भी रैनोवेशन की जरूरत है। इसीलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे इसका सर्वेक्षण करवाएं कि बिहार तथा देश के दूसरे भागों में जो तालाब हैं, जो बड़ी-बड़ी झीलें हैं, जो भर गई हैं, उनकी सफाई हो। हमारे यहां एक शब्द व्यवहार किया जाता है, उराही, उसकी उराही कराई जाए जिससे कि पानी का उसमें संचयन हो सके। पीने के पानी की समस्या है। आजकल जो बड़ी-बड़ी कम्पनीज हैं, वे भी पानी का बहुत दोहन कर रही हैं। वे दोहन करती हैं, उसके बाद उनकी फैक्टरी से जो पानी निकलता है, उसका ट्रीटमेंट वे नहीं करते हैं, उसका शुद्धिकरण नहीं करते हैं उससे दो नुकसान होते हैं। एक तो शुद्धिकरण न होने की वजह से अच्छा पानी नहीं मिलता और दूसरा नदियों में जब वह जल जाता है तो नदियों को भी प्रदूषित करता है। उनके विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिए। अगर वे नियम का पालन नहीं करते हैं, अगर वे ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। महोदया, मैं फिर कहना चाहता हूं कि आज सिर्फ दो राज्य लड़ रहे हैं कल ऐसी बात हो सकती है कि पानी के लिए दो देश लड़ेंगे मुझे तो लगता है कि शायद अगली बड़ी वार पानी के ही सवाल पर न हो जाए। महोदया, आप मेरी ओर बार-बार देख रही हैं, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि—बिहार की समस्याओं की ओर आप ध्यान दे रहे हैं मैं आप दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त करता हूं—आगे भी इस समस्या का तुरंत समाधान नहीं होने जा रहा है मैं यह जानता हूं मगर आप लगातार इसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे तो एक न एक दिन इस समस्या का समाधान निकलेगा और मैं चाहूंगा कि आपकी सरकार इस यूपीए की सरकार, जिन्होंने इसको शुरू किया है, आप ही की सरकार में यह काम हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

DR. K. KASTURIRANGAN (Nominated): Thank you, Madam Chairperson. I have only three points to make on this aspects. One is relating to an area of concern that is slowly developing, and that is related to the Himalayan Glaciers. Madam Chairperson, the Himalayan Glaciers is one of the very unique water body systems in the world and outside the polar cap, probably, one of the largest. They occupy something like 17 per cent of the Himalayan area, and there are something like 15,000 of them. What is the significance of these glaciers; firstly, they control the Himalayan ecology, and secondly, they supply water to some of the largest river systems in the North, that is, the Indus, the Ganges, the Brahmputra, and their tributaries. What is disturbing about the glacier systems is that in the recent past, there has been a recession in the level of snow in these glaciers. This has been seen consistently over the last 20 years, when this monitoring was being carried out. Some of the glaciers have receded

as much as a kilometre. So, obviously, when this kind of a recession takes place, there are going to be changes in the water content in some of the major rivers of the Northern system. Now, the implications of the changes are as follows. One is that there could be an increased flow of water in the initial phase of warming because of the fact that you have more ice and snow melting, and contributing to the river water. On the other side, after a long time, maybe, after a decade or two, one could again see that there is less amount of snow available and there could be a reduced water content in the river system. Considering that the Indo-Gangetic plain, in the words of Dr. Norman Borlog, is such a massive area, in alluvial plain, which could virtually support the entire earth in terms of the food requirements, if properly managed, there is cause for concern simply because if there are changes in the water flow in these river systems, it could affect the productivity of the land around that location, i.e. the Indo-Gangetic plain. So, what I am suggesting for the kind consideration of the hon. Minister of Water Resources is that we should carry out a very detailed assessment of this recession of the snow, create atlases related to the glacier, model the implications of the glacier melting, look at the near term issues related to the increased water flow into the river systems and also assess the questions of reduced potential, reduced water flow in the years to come and so on. Thus probably, a major effort needs to be mounted, much more than what is presently going on in the Ministry of Water Resources. This is one aspect.

The second aspect is, we have today a method of monitoring the water systems.

PROF. P.J. KURIAN (Kerala): Can you also explain why this recession is taking place?

DR. K. KASTURIRANGAN: It is because of the global warming...(*Interruptions*)...

PROF. P.J. KURIAN: That is the only reason.

DR. K. KASTURIRANGAN: Yes. Presently, of course, there are deforestation and many other kinds of local ecological system perturbations; that are also a cause for concern. So, one has to totally understand the reasons for it. But today, one ascribes these two causes for the level of changes. This is the only major glacier in the tropical region of the world.

That also makes it a unique system in terms of the impact of global warming on the glacier. For example, these glaciers in Switzerland and other places in Europe are less affected because of less changes in the temperature. They are much colder. But you have a tropical glacier in this part of the Himalayas.

PROF. P.J. KURIAN: The depletion of snow is very dangerous, ultimately disastrous.

DR. K. KASTURIRANGAN: The second point that I would like to mention, Madam Chairperson, is that we have today an excellent system of data collection from ground, aerial surveys and space. We should be able to locate the surface water bodies and even look at their depletion in terms of their capacity, desilting aspects. Secondly, we can also look at the ground water. You can look at the snowfall. You can look at many other aspects of the hydrological cycle. Now, the suggestion here is that we should make an assessment of the water resources. My suggestion is that we should do a water resources census after every five years, which will give us the health of the water resources in the country. Maybe, once in five years we can do a water resources census, exactly in the same way as what we do for demographic census as well as land resources census. So, this could be a third dimension of this kind of effort. Probably, a synchronisation of all the three could be a very useful thing in terms of database, which would lead to several aspects of decision making for development in this country.

The last point which I would like to make is that we have something like 4,000 billion cubic metres of water that precipitates over this country. We have something like 1,130 billion cubic metres of water. That is the potential water which is available. An amount of 600 billion cubic metres of water is currently used. If we look at the projection from today to 2025 and then to 2050, when our population, in the normal circumstances, would be something like 1,640 million, we will find that the requirement of water would go up from the current 600 billion cubic metres to 1,150 billion cubic metres and, finally, roughly to 1,500 billion cubic metres. Now, we have to have a very clear-cut road map. Most of the projects to increase the utiliable water resources in the sub-continent are going to be fraught with long gestation periods. So, one has to make an assessment of this and see what is going to be the road map so that we could meet the target required,

which is something like 1,150 billion cubic metres by 2025 and 1,500 billion cubic metres by 2050. How are we going to reach these targets? We have to make an assessment. What are the options available? The option, of course, would be groundwater recharging. One has to do the water cycling. One has to look at what level is inter-basin water transfer critical. I must say, in the context of inter-basin transfer, that there are areas in the country where there is not much of an option, except through inter-basin transfer, to make sure that we have the right amount of water. The ecological aspect, certainly, will have to be addressed. There are no soft options. There are only hard options. We have to look into that.

On the whole, certainly, India has enough potential in terms of water that is available. If one takes a reasonable fraction of total precipitation, say 35 per cent of its, still it could meet the requirement up to 2050 based on certain rationale for per capita requirements, industrial as well as agricultural uses. What is important is to have a very clear-cut management plan and developmental plan spread over something like 40-50 years. I am sure, the Water Resources Ministry would address this question. But there is a sense of urgency to it. Thank you.

श्री संजय राजाराम राउत (महाराष्ट्र): मैडम, आज इस सदन में, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। इससे एक बात तो साफ हो गई है और सबका यह मानना भी है कि पानी एक राष्ट्रीय विषय है, मुद्दा है। यहां पर केशुभाई पटेल जी ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है और अच्छे सुझाव भी दिए हैं। मैं उनके सुझावों का स्वागत करता हूं। मैडम, आजादी के 55 साल बाद भी, हम इस सदन में पानी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने दुश्मनों से लड़ने के लिए अणु-अस्त्र बना लिए हैं, लेकिन देश की जनता आज भी राज्य-राज्य, गांव-गांव में पानी के लिए झगड़ रही है। यह कोई अच्छा चित्र नहीं है। मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि आज देश में धर्मांधता, आतंकवाद और बढ़ती हुई आबादी से भी बड़ा संकट पानी का है। पंजाब हरियाणा से लड़ रहा है और कर्नाटक तमिलनाडु से लड़ रहा है। यह लड़ाई सिर्फ राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गांव-गांव इस लड़ाई की चपेट में आए हैं। मैडम, इस लड़ाई की असली वजह हमारी दोषपूर्ण जल नीति है। एक तरफ पानी को लेकर पूरे देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है और उसकी शुरूआत हो रही है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आज तक जो काम आई॰एस॰आई॰, अल-कायदा या लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन नहीं कर सके, वह काम पानी की कुछ बूंदें कर जाएंगी और एक दिन पानी के लिए देश में बिखराव आ जाएगा। अगर हमने समय रहते पानी और अपनी जल नीति की ओर जल नियोजन नहीं किया

तो पानी के लिए लोग एक-दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। मैडम, मैं महाराष्ट्र से आया हूं और महाराष्ट्र में आज छोटे-छोटे गांव पानी के लिए एक-दूसरे से भिड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि पानी के लिए जब राजनीति शुरू होती है तो बहुत गंभीर समस्या पैदा होती है। चंद वोटों की खातिर नेता अगर किसी ओर के हिस्से का पानी रोक लेते हैं और अपनी जनता से कहते हैं कि देखो, मैंने उस राज्य को पानी नहीं दिया, अब तुम मुझे अपने वोटों के काबिल समझो, तो यह बहुत दुख की बात है। हमारी संस्कृति, हमारे धर्म में प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, लेकिन राजनीति में प्यासे को प्यासा छोड़ देना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई है। मैडम, देश का अस्सी फीसदी पानी हम खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका पचास प्रतिशत पानी गलत तरीकों से इस्तेमाल करने के कारण व्यर्थ चला जाता है। इससे बाढ़ पीड़ित इलाकों में भी सात-आठ महीनों में सूखा आ जाता है। मैडम, आज बरसात का समय नहीं है, फिर भी महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बरसात हो रही है। इस बरसात के बावजूद भी महाराष्ट्र के कई गांव ऐसे हैं, जहां पीने का पानी टैंकर से आता है। कुछ गांव नहीं, बल्कि लगभग आधा महाराष्ट्र टैंकर से पानी पी रहा है। मुझे लगता है कि यही हाल आधे देश का है। बाढ़ आती है, चली जाती है, पानी बह जाता है और मानसून से पहले ही हम पानी के लिए चिंतित हो जाते हैं। यह चक्र चलता ही रहेगा। मैडम, आज से पच्चीस साल पहले देश में यह स्थिति थी कि पानी के लिए किसान को जमीन के नीचे सिर्फ छह फीट खुदाई करनी पड़ती थी, आज देश में कई जगह ऐसी स्थिति है कि सौ फीट नीचे तक खुदाई करने के बाद भी पानी नजर नहीं आता है। पिछले पैंतीस सालों में थार के रेगिस्तान में, गुजरात और देश के कई हिस्सों में पानी का स्तर दो सौ मीटर के नीचे भी जा चुका है। देश की आधी आबादी भू-जल पर निर्भर है। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले दिनों में भारत में गिरते भू-जल स्तर के कारण गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। यह कहानी सिर्फ गुजरात, थार या महाराष्ट्र जैसे इलाकों तक सीमित नहीं है, पंजाब जैसे सुजलाम् प्रदेश भी इस समस्या की चपेट में आने लगे हैं। वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट नाम की एक संस्था ने तो चेतावनी दी है कि वर्ष 2025 तक पंजाब में गंभीर जल संकट पैदा होगा, क्योंकि पंजाब का भू-जल स्तर भी आज सौ मीटर से नीचे जा चुका है। यह एक आघातकालीन स्थिति है और इसका सामना भी इसी दिशा में करना होगा। मैडम, हिंदुस्तान में जल स्रोतों की उपलब्धता और जल नियोजन की विषमता पर खास ध्यान देने की जरूरत है। हिन्दुस्तान में हर साल औसतन 1150 मिलीमीटर बारिश होती है, यानी 40 इंच, लेकिन इसका प्रमाण भी भारी विषमता लिए हुए है। एक तरफ चेरापूंजी है, जहां 12,500 मिलीमीटर बारिश होती है, यानी 500 इंच होती है तो दूसरी तरफ राजस्थान के जैसलमेर में सिर्फ 130 मिलीमीटर, यानी 4 या 5 इंच बारिश होती है। देश में ज्यादातर बारिश जून से सितम्बर महीने तक होती है, बाकी आठ महीने सूखा रहता है। इस विषमता को देखते हुए हमें हमारी जल नीति पर गंभीर विचार करना जरूरी है। अगर हमने इस विषमता को दूर करने की दिशा में जल्द से जल्द

कदम नहीं उठाया तो देश में पानी के लिए अंदरूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी और संबंधों में आपसी तनाव आ जाएगा। पिछले साल पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने पड़ोसी राज्यों को पानी देने से इंकार कर दिया, इससे क्या हासिल हो गया और ऐसा कब तक होता रहेगा? हमें अपनी जल नीति पर पुनर्विचार करना होगा। इस समस्या का समाधान राजनीति से प्रेरित होकर नहीं हो सकता। हमें राजनीति से हटकर हमारी राष्ट्रीय जल-नीति पर विचार करना चाहिए। मैडम, हमारे जल स्रोत, उनकी उपलब्धता और पानी के इस्तेमाल करने के तरीके मेल नहीं खाते जोकि एक गंभीर बात है। अगर हमारी जल-नीति का यही हाल रहा तो आने वाले 20 सालों में हमें पानी import करना पड़ेगा। मैडम, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट का मानना है कि सन् 2025 में हिंदुस्तान उन 29 देशों में से एक होगा जो अपने पानी की जरूरत विदेशों से खरीदकर पूरी करेगा।

मैडम, पानी की समस्या कई सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। जहां पानी कम है, उन इलाकों में पानी के लिए सारी मशक्कत महिलाओं को करनी पड़ती है। महिलाएं और छोटी-छोटी बच्चियां पैदल चलकर 8-10 मील दूर से पानी लेकर आती हैं। यह चित्र देश की सामाजिक समता को नींव से उखाड़ फेंकती है। हम अपनी जल-नीति में जब जल स्रोतों में निजीकरण की बात करते हैं तब इन महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करते हैं और इन लड़कियों और छोटी-छोटी बच्चियों को उनकी शिक्षा के अधिकार से दूर करते हैं। हमारे जल स्रोतों पर हमारे देश की महिलाओं का पहला और स्वाभाविक अधिकार है न कि विदेशी कंपनियों का। मेरी पार्टी यह मानती है कि जल-नीति में जिस आरक्षण शब्द का उपयोग किया गया है, वह आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। मैडम, गांव की महिलाएं अपने गांव के जल स्रोत की पहली और आखिरी हकदार हैं। जल स्रोत की रक्षा और उसकी वृद्धि के बारे में एक महिला से ज्यादा न कोई जानता है और न कोई उसकी फिक्र करता है।

मैडम, भविष्य में पानी के इस्तेमाल पर कुछ पाबंदिया लगाना जरूरी है। हमारे यहां एक कहावत है, ''पानी की तरह पैसा बहाना'' यानी पानी की कोई कीमत नहीं है। मुझे यकीन है कि स्थितियां अगर यहीं रहीं तो आने वाले समय में पानी बहाना नसीब नहीं होगा और हम पानी के लिए खून और पैसा जरूर बहा सकेंगे। अगर हमें यह रोकना है तो बड़े किसानों से लेकर रेस्ट्रां और होटल मालिकों तक-सभी पर अंकुश लगाना पड़ेगा। हमारे यहां बड़े-बड़े किसान बड़ी-बड़ी मोटरों से ज्यादा-से-ज्यादा पानी खींचते हैं। होटल और रेस्ट्रां में पानी का एक घूंट पीने के बाद गिलास बदल दिए जाते हैं। पानी के इस अपव्यय को कानूनी अपराध मानना चाहिए तभी हम कुछ पानी का संचय कर सकेंगे और कुछ पानी बचा सकेंगे। मैडम, जमीन के नीचे पानी का जो स्रोत है, उसकी भी अपनी सीमा है। आज देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां के जल स्रोतों को हमने पानी खींच-खींचकर सुखा दिया है। हम कई दशकों से मानकर चलते हैं कि बांध बनाने से हमारे पानी की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। मैडम,

6.00 P.M.

मैं यहां एक उदाहरण देना चाहूंगा। वर्ष 2001 में गुजरात में सूखा पड़ा था तब कच्छ, सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात के 143 बांधों में से 107 बांध सूख गए थे। इसका अर्थ स्पष्ट है कि बड़े किसान और इंडस्ट्रीज पर उनके पानी खींचने के बेलगाम तरीकों पर अंकुश नहीं लगा पाए हैं और जब तक यह आदत हम नहीं बदलेंगे तब तक बड़े-से-बड़े और ज्यादा बांध हमारी जल समस्या का समाधान नहीं बन सकते। मैडम, छोटे-छोटे तालाब बनाकर बारिश का पानी जमा कर हम भू-जल स्तर बढ़ा सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने भी यही तरीका अपनाया था। आज अगर इस देश में किसी बात की सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वह जल क्रांति की है। हमें जल व्यवस्थापन यानी water management और जल नीति यानी water policy के बारे में लोगों में सजगता पैदा करनी चाहिए और जल क्रांति का यही पहला चरण होगा। मगर जल क्रांति यहीं पूरी नहीं होगी। इस बारे में हमें एक जल साक्षरता अभियान चलाना होगा जिसमें आम लोगों को शामिल किया जाना होगा क्योंकि सिर्फ सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों से हम अपने जल स्रोतों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। मैडम, हमारे यहां आज भी लोग यह मानते हैं कि जल स्रोत अक्षय हैं और ये निरंतर चलते रहेंगे। हमें इस दृष्टिकोण को बदलना होगा तभी इस देश में जल क्रांति पूरी होगी। इस जल क्रांति में बरसात के पानी को संग्रह करने के नए उपाय ढूंढने होंगे, पुरानी पाइप-लाइनें बदलनी होंगी, illegal connections रोकने होंगे और नदियों को जोड़ना होगा। आज सबसे बड़ी बात यह होगी कि पूरे देश में जल स्रोतों के बारे में हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। मैं चाहूंगा कि आज से हम अपनी जल नीति को जल क्रांति अभियान के नाम से पुकारे क्योंकि नीतियां तो सरकार बनाती है, लेकिन क्रांति लोगों द्वारा लायी जाती है। हमें लोगों को जागरूक कर इस बदलाव को लाना चाहिए और इस नीति को जल क्रांति में परिवर्तित करना चाहिए। इस देश के समाज, तालाब, प्रकृति और वन्य जीवन पानी से जुड़े हुए हैं। हमें समाज के लिए पारंपरिक ...(समय की घंटी)... और आधुनिक तकनीक के मेल से महिलाओं और सामुदायिक तरीके से बनाई गई जल-नीति चाहिए, जिसमें सरकार से ज्यादा लोगों का अधिकार होगा और जल और नीति अलग नहीं होगी और लोग अपना पानी पैसे की तरह तोलेंगे और पैसे के लिए पानी बहाने की आदत छोड़ देंगे। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी): धन्यवाद। श्री नारायणसामी जी, माननीय मंत्री जी को वक्तव्य भी रखना है, तो आप थोड़ा उसी हिसाब से समय लीजिए।

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, if you permit me, I can lay my statement on the Table.

SHRI V. NARAYANASAMY: Yes, Madam. I can speak after that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SARLA MAHESHWARI): If the House so permits...(*Interruptions*)... No. we have to finish the discussion today itself. Tomorrow, we will have the reply from the Minister.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Madam, how long will it take?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SARLA MAHESHWARI): Only two speakers are left. So don't worry. We will be able to finish it.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Then, let the discussion be over.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Whenever the House agrees, I will do it. You fix the day. I have no problem.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam,...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी) : नारायणसामी जी, अगर आप बैठें तो मैं माननीय मंत्री जी से सदन की अनुमति से यह निवेदन कर सकती हूं कि वो चाहे तो अपने बयान को सदन के पटल पर रख दें।

SHRI YASHWANT SINHA: Madam, I do not know what the Minister is going to speak. We are not privy to it. This is a highly controversial issue. I would prefer that the Minister reads the statement.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I have no problem. I can read it.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सरला माहेश्वरी) : अगर आप इच्छुक हैं तो...(व्यवधान)... आप पहले पढ़ दीजिए। बाद में हम लोग... ।

STATEMENT BY MINISTER

Affidavits filed on Behalf of Union of India in the Writ Petition (C) 270 of 2004 filed By K.G. Dhananjay Chauhan Versus Union of India and Others

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, in the last few days, various statements have been carried in the media in respect of the affidavits filed on behalf of the Union of India (UO) in the Writ Petition (C) 270 of 2004 filed by K.G. Dhananjay Chauhan *versus* Union of India and others. I would like to place the facts on record.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

The Writ Petition had been filed in the Supreme Court on 15th June, 2004 as a Public Interest Litigation. The Writ Petition is primarily based on the report of the Comptroller and Auditor General (CAG) No. 7A of 2001 which deals with the special audit of cases of procurement done for